



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2005/आषाढ़ 10, 1927

No. 292]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2005/ASADHA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए1.....जुलाई,....., 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना सं. 1/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005.

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2005, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[Notification No. 1/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V.P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियुक्त करती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिल कर बनेगा और केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[अधिसूचना सं. 2/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints an Adjudicating Authority to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under the said Act. The Adjudicating Authority shall consist of a Chairperson and two Members and shall function within the Department of Revenue, Ministry of Finance of the Central Government with Headquarters at New Delhi.

[Notification No. 2/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 438(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की नई दिल्ली न्यायपीठ सम्पूर्ण भारत में उक्त अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगी।

[अधिसूचना सं. 3/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (5) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby specifies that the New Delhi Bench of the Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the said Act shall exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under the said Act over the whole of India.

[Notification No. 3/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

स.का.पि. 439(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए नई दिल्ली में अपील अधिकरण स्थापित करती है।

[अधिसूचना सं. 4/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

बी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby establishes an Appellate Tribunal at New Delhi to hear appeals against the orders of the Adjudicating Authority and the authorities under the said Act.

[Notification No. 4/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 440(अ).—केन्द्रीय सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15) की धारा 49 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई 2005 से वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और इसके परन्तुक, धारा 13, धारा 26 की उप-धारा (2) और धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अनन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और उक्त निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (5), धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 48, धारा 49 की उप-धारा (2), धारा 66 और धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी समवर्ती रूप से प्रयोग करेगा ।

[अधिसूचना सं. 5/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005,

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints, with effect from the 1st day of July, 2005, the Director, Financial Intelligence Unit, India, under the Ministry of Finance, Department of Revenue, as the Director to exercise the exclusive powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of section 12 and its proviso, section 13, sub-section (2) of section 26 and sub-section (1) of section 50 of the said Act and the said Director, Financial Intelligence Unit, India, shall also concurrently exercise powers conferred by sub-section (3) and sub-section (5) of section 26, section 39, section 40, section 41, section 42, section 48, sub-section (2) of section 49, section 66 and section 69 of the afore-said Act.

[Notification No. 5/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 441(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15) की धारा 49 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2005 से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) के अधीन उक्त तारीख से ठीक पहले निदेशक, प्रवर्तन का पद धारण करने वाले अधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 5 धारा 8, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 26 की उप-धारा(1), धारा 45, धारा 50, धारा 57, धारा 60, धारा 62 और धारा 63 के अधीन प्रदत्त अनन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त निदेशक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) उप-धारा (4) और उपधारा (5), धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 48, धारा 49, धारा 66 और धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी समवर्ती रूप से प्रयोग करेगा।

[अधिसूचना सं. 6/2005/फा. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 441(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 49 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints, with effect from the 1st day of July, 2005, the Director of Enforcement holding office immediately before the said date under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), as the Director to exercise the exclusive powers conferred under section 5, section 8, section 16, section 17, section 18, section 19, section 20, section 21, sub-section (1) of section 26, section 45, section 50, section 57, section 60, section 62 and section 63 of the said Act and the said Director shall also concurrently exercise powers conferred by sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 26, section 39, section 40, section 41, section 42, section 48, section 49, section 66 and section 69 of the afore-said Act.

[Notification No. 6/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिधारण की अवधि से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति, और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति और इसके प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं,—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) “प्राधिकृत अधिकारी” से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो उस उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो जिसे अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;
- (ग) “प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 48 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के प्रवर्गों में से अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (घ) “अभिहित अधिकारी” से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “सामग्री” से, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके आधार पर उसने कारण अभिलिखित किए हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है

(i) अनुसूची के भाग क के पैरा 1 और भाग ख के अधीन किसी अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट ; या

(ii) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन किसी अपराध के संबंध में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए फाइल की गई कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई परिवाद ;

(छ) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “सामग्री” से प्राधिकारी के कब्जे में ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके आधार पर उसने कारण अभिलिखित किए हैं ;

(ज) “स्थान” से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां धन शोधन के अपराध करने का कार्य किया जाता है और जिसके अंतर्गत कोई अन्य स्थान भी है चाहे उसमें कोई क्रियाकलाप किया जाता है या नहीं, जिसमें ऐसा क्रियाकलाप चलाने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि किसी प्राधिकारी को समनुदेशित उस क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले ऐसे कार्य से संबंधित उसके अभिलेखों में से कोई अभिलेख रखा जाता है या उसकी संपत्ति का कोई भाग रखा जाता है या जिसकी बाबत अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, जिसे क्रमशः अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) के अधीन क्षेत्र को समनुदेशित किया जाता है ;

(झ) “अभिलेख” के अंतर्गत पुस्तकों के प्ररूप में रखे गए या किसी कंप्यूटर या टेप या डिस्क में भंडारित अभिलेख या किसी भी प्रकार की उंतारी गई सूचना चाहे सामान्य या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त और ऐसे अन्य दस्तावेज भी हैं जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकेंगे

(ज) “अनुसूची” से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ट) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति अग्रेषित करने की रीति -(1) यथास्थिति,

निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी आदेश की प्रति और सामग्री की एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका, आदेश और सामग्री के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा । वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसी अनुक्रमणिका, आदेश और सामग्री को अग्रेषित करते समय मुहरबंद लिफाफे में एक पत्र भी लिखेगा ।

(2) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी लिफाफे में उसे मुहरबंद करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-I में एक पावती की पर्ची रखेगा ।

(3) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, मुहरबंद लिफाफे पर अग्रेषण का संदर्भ संख्यांक और तारीख उपदर्शित करेगा ।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर “गोपनीय” और “केवल प्राप्त करने वाले द्वारा ही खोला जाए” चिह्नित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का उसके नाम सहित पूरा पता उल्लिखित किया जाएगा ।

(5) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद लिफाफे को बाह्य मुहरबंद लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-III में एक पावती पर्ची रखेगा ।

(6) बाह्य लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता

बाह्य मुहरबंद लिफाफे पर उल्लिखित किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश की एक प्रति और सामग्री अग्रेषित किए जाने के तुरंत पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

4. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की

बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने की रीति,-(1) प्राधिकारी, सर्वेक्षण की

बाबत कारणों की प्रति और सामग्री की एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका, कारणों और ऐसी सामग्री के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और न्याय निर्णायक प्राधिकारी को ऐसी अनुक्रमणिका, कारणों और सामग्री को अग्रेषित करते समय मुहरबंद लिफाफे में एक पत्र भी लिखेगा

(2) प्राधिकारी, लिफाफे में उसे मुहरबंद करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II में एक पावती की पर्ची रखेगा ।

(3) प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे पर अग्रेषण का संदर्भ संख्यांक और तारीख उपदर्शित करेगा।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर “गोपनीय” और “केवल प्राप्त करने वाले द्वारा ही खोला जाए” चिह्नित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का उसके नाम सहित पूरा पता उल्लिखित किया जाएगा ।

(5) प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को बाह्य मुहरबंद लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-III में एक पावती पर्ची रखेगा ।

(6) बाह्य लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता बाह्य मुहरबंद लिफाफे पर उल्लिखित किया जाएगा ।

- (7) प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित किए जाने के तुरंत पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेशों की प्रति और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारणों की प्रति और सामग्री की प्राप्ति की पावती, --

- (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय का अभिहित अधिकारी, प्ररूप-II के साथ बाह्य मुहरबंद लिफाफे के प्राप्त होने पर, प्ररूप-II को सम्यक् रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखकर अग्रेषित करेगा। प्ररूप -II को, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर, मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी।
- (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को खोलने पर प्ररूप -I को सम्यक् रूप से भर कर और हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखकर अग्रेषित करेगा। प्ररूप-I को, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत प्राधिकारी या प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर सामग्री के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सर्वेक्षण की बाबत सामग्री के साथ कारणों की प्रति की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी।
- (3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए सामग्री के साथ, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश की प्रति की प्राप्ति के ब्यौरे दर्शित करते हुए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे पावती पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर और राजेस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आदेश और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारण और सामग्री के प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् रजिस्ट्रों में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

6. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सामग्री तथा सर्वेक्षण की बाबत कारणों की प्रति और सामग्री प्रतिधारित करने की अवधि,-

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति और सामग्री तथा कारणों की प्रति तथा सामग्री को दस वर्ष की अवधि के लिए या, यदि दस वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व, -

- (i) अधिनियम की धारा 8 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ हो गई है तो ऐसी कार्यवाहियों के निपटारे होने तक ; या
- (ii) जहां अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपील अधिकरण को अपील की गई है वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक ; या
- (iii) जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उच्च न्यायालय में ऐसी कोई अपील की गई है वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक ;

जो भी पश्चात्पूर्ति हो, प्रतिधारित करेगा ।

7. निर्बचन,- यदि इन नियमों के निर्बचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वह विषय केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप- I

[नियम 3 का उपनियम(2) देखें]

पावती पर्ची .

क्रम संख्यांक.....

निदेशक /प्राधिकृत अधिकारी सेको बजे

[तारीख]

[समय]

.....पृष्ठों से युक्त सामग्री के साथ अनंतिम कुर्की आदेश
संख्यांक.....तारीख..... की एक प्रति प्राप्त की ।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख :

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

[निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी]

पता-----

प्ररूप- II

[नियम 4 का उपनियम (2) देखें]

पावती पर्ची

क्रम संख्यांक.....

.....सेको बजे

[प्राधिकारी का पदनाम जिससे प्राप्त हुआ]

[तारीख]

[समय]

कारणों और सामग्री से युक्तपृष्ठों के साथ पत्र संख्यांक

तारीख..... की प्रति प्राप्त की।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख :

.....
[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी]

[कार्यालय की मुहर]

[प्राधिकारी]पता-----

प्ररूप- III

(नियम 3 का उपनियम (5) और नियम 4 का उपनियम (5) देखें)

पावती पर्ची

क्रम संख्यांक.....

.....सेको.....बजे

(यथास्थिति निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी जिससे प्राप्त हुआ) [तारीख]

[समय]

एक मुहरबंद लिफाफा संख्यांक.....तारीख.....प्राप्त किया ।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी का नाम)
[कार्यालय की मुहर]

[यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी]

पता-----

[अधिसूचना सं. 7/2005/फा. सं. 6/2/2004-इ.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 428(1)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) and clause (l) of sub-section(2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the manner of forwarding a copy of the order of provisional attachment of property along with the material, and the copy of the reasons along with the material in respect of survey, to the Adjudicating Authority and its period of retention by the Adjudicating Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Manner of forwarding a copy of the Order of Provisional Attachment of Property along with the Material, and copy of the Reasons along with the Material in respect of Survey, to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

- (a) “Act” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
- (b) “authorised officer” means any officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of section 5 of the Act;
- (c) “authority” means an authority notified from among the classes of authorities specified in section 48 of the Act;
- (d) “designated officer” means an officer designated by the Adjudicating Authority for the purpose of sub-rule (1) of rule 4;
- (e) “Form” means forms appended to these rules;
- (f) “material” for the purposes of sub-section (1) of section 5 of the Act means any material in possession of the Director or the authorised officer, as the case may be, on the basis of which he has recorded reasons including –
 - (i) a report forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A and Part B of the Schedule; or
 - (ii) a police report or a complaint filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section (1) of section 36 of the

Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985
(61 of 1985) in relation to an offence under paragraph
2 of Part A of the Schedule;

- (g) "material" for the purposes of sub-section (1) of section 16 of the Act means any material in possession of the authority on the basis of which it has recorded reasons;
 - (h) "place" means a place where an act constituting the commission of the offence of money-laundering is carried on and includes any other place, whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are or is kept, falling within the limits of the area assigned to an authority or in respect of which an authority has been authorised by such other authority who is assigned the area under clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) of section 16 of the Act respectively;
 - (i) "records" include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information of any type whether expressed in ordinary or machine language and such other documents as may be useful for the purposes of these rules;
 - (j) "Schedule" means the Schedule to the Act;
 - (k) "section" means a section of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Manner of forwarding a copy of the order of provisional attachment of property along with the material under sub-section (2) of section 5 of the Act, to the Adjudicating Authority.** — (1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index of a copy of the order, and the material and sign each page of such index, order and the material and shall also write a letter while forwarding such index, order and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.
- (2) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall place an acknowledgement slip in Form-I appended to these rules inside the envelope before sealing it.
 - (3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.
 - (4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name, shall be mentioned on the sealed envelope with official seal.

- (5) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall place the sealed envelope inside an outer envelope along with an acknowledgement slip in Form-III appended to these rules.
 - (6) The outer envelope shall be sealed and the complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.
 - (7) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the order along with the material are forwarded to the Adjudicating Authority.
4. **Manner of forwarding a copy of the reasons along with the material in respect of survey under sub-section (2) of section 16 of the Act, to the Adjudicating Authority.** - (1) The authority shall prepare an index of a copy of the reasons and the material in respect of survey and sign each page of such index, reasons and the material and shall also write a letter while forwarding such index, reasons and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.
- (2) The authority shall place an acknowledgement slip in Form-II appended to these rules inside the envelope before sealing it.
 - (3) The authority shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.
 - (4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name, shall be mentioned on the sealed envelope with official seal.
 - (5) The authority shall place the sealed envelope inside an outer envelope along with an acknowledgement slip in Form-III appended to these rules.
 - (6) The outer envelope shall be sealed and the complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.
 - (7) The authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material in respect of survey are forwarded to the Adjudicating Authority.
5. **Acknowledgement of receipt of a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material in respect of survey by the Adjudicating Authority.** -
- (1) On receipt of the outer sealed envelope along with Form-II, the Adjudicating Authority or in his absence, the designator of the

office of Adjudicating Authority, shall forward Form-II duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding Form-II to the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, as a token of receipt of the sealed envelope.

- (2) The Adjudicating Authority shall, on opening of the sealed envelope, forward Form-I duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding of Form-I to the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, as a token of receipt of the copy of the order of provisional attachment of property along with the material and a copy of the reasons along with the material in respect of survey.
 - (3) Adjudicating Authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register and register showing details of receipt of a copy of the order of the Director or the authorized officer or the authority, as the case may be, along with the material for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the registers immediately on receipt of such order and the material and reasons and the material in respect of survey.
6. **Period of retention of a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material in respect of survey by the Adjudicating Authority.** – The Adjudicating Authority shall retain a copy of the order of provisional attachment of property and the material and a copy of the reasons and the material for a period of ten years, or, if before the expiry of the said period of ten years, –
- (i) any proceedings under section 8 of the Act have been commenced, until the disposal of such proceedings; or
 - (ii) where an appeal has been preferred to the Appellate Tribunal under section 26 of the Act, until the disposal of such appeal by the Appellate Tribunal; or
 - (iii) where an appeal has been filed in the High Court under section 42 of the Act, until the disposal of such appeal by the High Court;

whichever is later.

7. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM-I

[See sub-rule (2) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a copy of the provisional Attachment Order bearing number dated along with the material containing pages from the Director/the authorized officer on at [date]

.....
[time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....
[Name of the Adjudicating Authority]

To

[Office seal]

[Director or the authorised officer]Address _____

FORM-II

[See sub-rule (2) of rule 4]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a copy of letter No. dated
along with the reasons and the material containing pages from the
..... on at
[designation of the authority from whom received] [date] [time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....
[Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To

[Authority]Address _____

FORM-III

[See sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (5) of rule 4]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a sealed envelope bearing No.
dated..... from[Director or the authorized officer or the authority from whom
received as the case may be]on at.....
[date] [time]Signature of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority......
Name of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority.

[Office seal)]

To

[Director or the authorised officer
or the authority as the case may be]
Address :
.....

[Notification No. 7/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.पि. 443(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15)

की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिदत्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अधिदत्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002(2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन

नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रशासक” से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “कुर्की” से अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा संपत्ति का अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन का प्रतिषेध अभिप्रेत है ;

(ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) “आदेश” से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(छ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. अधिहृत संपत्ति की प्राप्ति.- प्रशासक अधिहृत संपत्तियों की प्राप्ति के समय ऐसी संपत्ति का अधिहरण करने वाले आदेश में उल्लिखित उसकी विशिष्टियों के प्रतिनिर्देश से ऐसी संपत्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करेगा ।

4. **अधिहृत संपत्ति का प्रबंधन.-** (1) जहां अधिहृत संपत्ति ऐसी प्रकृति की है कि कुर्की के स्थान से उसका हटाया जाना अव्यवहार्य है या उसके हटाए जाने में उस संपत्ति के मूल्य के अनुपात से अधिक व्यय अंतर्वर्तित है वहां प्रशासक कुर्की के स्थान पर उस संपत्ति के उचित अनुक्षण और अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) यदि अधिहृत संपत्ति नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में है तो प्रशासक उनको निकटतम सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा करवाएगा ।

(3) प्रशासक नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं जैसी जंगम संपत्ति की बाबत प्रविष्टियों के अभिलेखन के लिए प्ररूप 1 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर रखवाएगा ।

(4) प्रशासक इस नियम के उपनियम (3) में काथत जंगम संपत्तियों को जमा करने के बदले में, यथास्थिति, खजाने या बैंक से एक रसीद अभिप्राप्त करेगा ।

(5) प्रशासक इस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपत्तियों से भिन्न संपत्ति की बाबत प्रविष्टियों के अभिलेखन के लिए प्ररूप 2 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर रखवाएगा ।

5. **प्रशासक को सहायता.-** केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने में प्रशासक की सहायता के लिए समय-समय पर कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की, जैसा वह ठीक समझे, व्यवस्था कर सकेगी ।

6. **निर्वचन.-** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वह विषय केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप 1**[नियम 4 का उपनियम (3) देखिए]****अधिहृत संपत्ति (जंगम) का प्रबंधन रजिस्टर**

1. आदेश सं.
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख
3. संपत्तियों का वर्णन (मात्रा, राशि, अनुमानित मूल्य)
4. अभियुक्त का/के नाम और पता/पते
5. जहां संपत्तियां सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की गई हैं उस खजाने या बैंक का नाम और पता
6. खजाने या बैंक में अधिहृत संपत्तियों को जमा करने की तारीख और समय
7. खजाने या बैंक से अभिप्राप्त रसीद की तारीख सहित रसीद सं.
8. प्रशासक की टिप्पणियां

(प्रशासक के हस्ताक्षर)**प्रशासक का नाम और पदनाम****तारीख :****प्ररूप 2****[नियम 4 का उपनियम(5) देखिए]****अधिहृत संपत्ति (स्थावर) का प्रबंधन रजिस्टर**

1. आदेश सं.
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख
3. संपत्तियों का वर्णन

(भूमि की दशा में : क्षेत्र, सर्वेक्षण सं., प्लॉट सं., अवस्थान और पूरा पता । भवन की दशा में :

मकान सं., अवस्थान और पूरा पता) :

4. अभियुक्त का/के नाम और पता/पते

5. प्रशासक की टिप्पणियाँ

तारीख :

[अधिसूचना सं. 8/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 443(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules for receipt and management of confiscated properties, namely :—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
 - (c) "Administrator" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 10 of the Act;
 - (d) "attachment" means prohibition of transfer, conversion, disposition or movement of property by an order issued under Chapter III of the Act;
 - (e) "Form" means forms appended to these rules;
 - (f) "order" means an order made by the Adjudicating Authority under sub-section (6) of section 8 of the Act;

- (g) "section" means a section of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Receipt of confiscated property.** — The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order confiscating such property.
4. **Management of confiscated property.** — (1) Where the property confiscated is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of attachment.
- (2) If the property confiscated consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall cause to deposit them for safe custody in the nearest Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or State Bank of India or its subsidiaries or of any authorized bank.
- (3) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form I for recording entries in respect of moveable property, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables.
- (4) The Administrator shall obtain a receipt from the Treasury or the bank, as the case may be, against the deposit of moveable properties stated in sub-rule (3) of this rule.
- (5) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form II for recording entries in respect of property other than the properties referred to in sub-rule (3) of this rule.
5. **Assistance to the Administrator.** — The Central Government may provide from time to time such members of staff and other persons as it thinks fit to assist the Administrator in exercise of his powers and performance of duties under these rules.
6. **Interpretation.** — If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM I

[See sub rule (3) of rule 4]

Management of Confiscated Property (Moveable) Register.

1. Order number :
2. Date of receipt of properties :
3. Description of properties (quantity, amount, estimated value) :

4. Name(s) and address(es) of the accused :
5. Name and address of the Treasury or bank where the properties are deposited for safe custody :
6. Date and time of deposit of confiscated properties in the Treasury or bank :
7. Receipt number with date of the receipt obtained from the Treasury or bank:
8. Remarks of the Administrator :

(Signature of the Administrator.)

Name and designation of the
Administrator.

Date :

FORM II

[See sub-rule (5) of rule 4]

Management of Confiscated Property (Immoveable) Register.

1. Order Number :
2. Date of receipt of properties :
3. Description of properties :
(In case of land : area, survey number, plot number, location and complete address. In case of building : house number, location and complete address) :
4. Name(s) and address(es) of the accused :
5. Remarks of the Administrator:

(Signature of the Administrator.)

Name and designation of the Administrator.

Date :

[Notification No. 8/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 444(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ प्रदत्त धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य के अभिलेख रखने, उन्हें रखने की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने के समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुक्षण, अनुक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुक्षण) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) “ग्राहक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के साथ किसी वित्तीय संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगा है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसकी ओर से जो संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगा है ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है ;
- (ग) “निदेशक” से अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;
- (घ) “शासकीय रूप से विधिमाम्य दस्तावेज” से पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति, स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या बैंककारी कंपनी अथवा वित्तीय संस्था अथवा मध्यवर्ती द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है ;
- (ङ) “विहित मूल्य” से इन नियमों के अधीन विहित संव्यवहार का मूल्य अभिप्रेत है ;
- (च) “प्रधान अधिकारी” से, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती द्वारा अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) “संदेहास्पद संव्यवहार” से ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है चाहे उसे नकद में किया गया हो अथवा नहीं, जो किसी सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को-

- (क) यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है कि इसमें किसी अपराध के आगम अंतर्वर्तित हो सकते हैं ; या

- (ख) किसी असामान्य या अनुचित रूप से जटिल परिस्थितियों में किए गए प्रतीत होते हैं ; या
- (ग) बिना किसी आर्थिक संगतता या सद्भावपूर्ण प्रयोजन के प्रतीत होते हैं ;

(ज) “संव्यवहार” के अन्तर्गत जमा करना, निकालना, निधियों का विनिमय या अंतरण चाहे किसी भी मुद्रा में हो, चाहे नकद या बैंक में हो, संदाय आदेश या अन्य लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य अभौतिक साधन द्वारा है ।

- (2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है ।

3. अंतरण के अभिलेखों (प्रकृति और मूल्य) का अनुसरण -

- (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती निम्नलिखित अभिलेख रखेंगे,-

- (क) दस लाख रुपए या किसी विदेशी करेंसी में उसके समतुल्य से अधिक मूल्य के सभी नकद संव्यवहार ;
- (ख) नकद संव्यवहारों की संपूर्ण श्रृंखला जो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और जिनका मूल्य दस लाख रुपए या किसी विदेशी करेंसी में उसके समतुल्य से कम आंका गया है, जहां संव्यवहारों की ऐसी श्रृंखला एक मास के भीतर की जाती है ;
- (ग) ऐसे सभी नकद संव्यवहार जहां कूटरचित या कूटकृत मुद्रा नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग किया गया है और जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना की गई है ;
- (घ) सभी संदेहास्पद संव्यवहार चाहे उन्हें नकद अथवा निम्नलिखित द्वारा किया गया है या नहीं और :
 - (i) किसी भी खाते में या उसमें से, चाहे उन्हें किसी भी मुद्रा किसी भी नाम से प्रति निर्दिष्ट किया गया है और जिन्हें निम्नलिखित द्वारा रखा गया है, जमा और क्रेडिट, निकाला जाना ;
 - (क) तृतीय पक्षकार बैंकों सहित बैंकों, संदाय आदेशों, मांग देय ड्राफ्टों, रोकड़िया बैंकों या इलेक्ट्रॉनिक रसीदों सहित धन संदाय कि किसी अन्य लिखित या क्रेडिटों और इलेक्ट्रॉनिक संदायों या जमा, या
 - (ख) यात्री बैंकों, या
 - (ग) यथास्थिति, समान बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती में एक खाते में से अंतरण जिसके अंतर्गत अस्मदीय और भवदीय खाते भी हैं, या
 - (घ) अन्य कोई रीति में चाहे उसका जो भी नाम निर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती द्वारा किसी भी करेंसी में रखे गए किसी गैरमौद्रिक खाते जैसे डी-मेट खाता, प्रतिभूति खाते में से जमा या नामे ;

(iii) भारत या विदेश से अपने ग्राहक या गैर ग्राहकों के पक्ष में धन अंतरण या प्रेषण का संव्यवहार या तृतीय पक्षकार के हिताधिकारियों को भारत या विदेश में जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा किसी भी करेंसी में अपने खाते में संव्यवहार भी है :-

- (क) संदाय आदेश, या
- (ख) रोकड़िया चैक, या
- (ग) मांग देय ड्राफ्ट या
- (घ) तार या वायर अंतरण या इलेक्ट्रानिक प्रेषण या अंतरण, या
- (ङ) इंटरनेट अंतरण, या
- (च) ऑटोमैटिड समाशोधन गृह प्रेषण, या
- (छ) लॉक बक्स चालित अंतरण या प्रेषण या
- (ज) जमा के लिए प्रेषण या इलेक्ट्रानिक कार्ड का भरण, या
- (i) किसी अन्य रीति से धन का अंतरण; चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

(iv) निम्नलिखित द्वारा उधार और अग्रिम जिसमें जमा या उधार स्थानापन्न, विनिधान और समाश्रित दायित्व भी है :

(क) जैसे-वाणिज्यिक कागजपत्र, निक्षेप प्रमाण पत्र, अधिमानी शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूति सहभागिता, अन्तर बैंक सहभागिता या प्रतिभूति में कोई अन्य विनिधान जैसे उधार लिखतों का अभिदाय या वैसे ही चाहे किसी प्ररूप में और नाम से निर्दिष्ट हो, या

(ख) बिलों, चैकों और अन्य लिखतों के क्रय या पराक्राम्य, या

(ग) विदेशी मुद्रा संविदा, करेंसी, ब्याज दर और वाणिज्या तथा कोई अन्य व्युत्पन्न लिखत चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या

(घ) प्रत्यय पत्रों, प्रत्यय पत्रों का समकक्ष, प्रत्याभूति, आश्वासन पत्र, शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और निपटान के लिए कोई अन्य लिखत और/या प्रत्यय समर्थन ;

(v) बिलों, चैकों, लिखतों या संग्रहण के किसी अन्य रीति चाहे वह किसी भी नाम से निर्दिष्ट हो, के संग्रहण, द्वारा किसी करेंसी में संग्रहण सेवाएं ।

4. सूचना अंतर्विष्ट करने वाले अभिलेख - नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी :-

- (क) संव्यवहारों की प्रकृति ;
- (ख) संव्यवहार की राशि और वह करेंसी जिसमें इसे अंकित किया गया है ;
- (ग) वह तारीख जिसको संव्यवहार किया गया था ; और
- (घ) संव्यवहार के पक्षकार ।

5. सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति - (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया और रीति के अनुसार नियम 3 में निर्दिष्ट अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहारों के संबंध में हार्ड और सॉफ्ट कॉपियों में सूचना रखेंगे।
- (2) प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती ऐसे रूप में और ऐसे अंतरालों, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, पर ऐसी सूचना रखने के लिए आंतरिक तंत्र का सृजन करेंगे।
- (3) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करे।
6. अभिलेखों का प्रतिधारण - नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों को, ग्राहक और यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती के बीच हुए संव्यवहारों की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।
7. सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और रीति - यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, निदेशक को प्रधान अधिकारी के नाम, पदनाम और पते की संसूचना देगा।
- (2) प्रधान अधिकारी, यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निदेशक को नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूचना की एक प्रति प्रधान अधिकारी द्वारा शासकीय अभिलेख के लिए धारित की जाएगी।
- (3) प्रत्येक बैंककारी कंपनी वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना को ऐसे रूप में और ऐसे अंतरालों, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, पर ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक तंत्र का सृजन करेंगे।
- (4) प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करे।
8. निदेशक को सूचना प्रस्तुत करना - यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती का प्रधान अधिकारी, प्रत्येक मास निदेशक को नियम 3 में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहारों की बाबत, जो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न हैं, सूचनाएं आगामी मास की 7 तारीख तक देगा:
- परंतु नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में सूचना शीघ्रता से, जो ऐसे संव्यवहार के होने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अपश्चात् नहीं होगा, लिखित में या फैक्स द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डाक से निदेशक को दी जाएगी।
9. ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन - (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती किसी खाते को खोलते समय या इसके साथ किसी संव्यवहार के करने के समय ग्राहक की पहचान के अभिलेखों और ग्राहक का वर्तमान पता या पत्तों, जिसके अन्तर्गत स्थायी पता या पते हैं, ग्राहक के व्यापार की प्रकृति और उसकी वित्तीय प्रास्थिति का सत्यापन करेगी और उनको रखेगी।

परंतु जहां ग्राहक की पहचान का सत्यापन, खाता खोलने के समय या किसी संव्यवहार के करने के समय संभव न हो, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती की पहचान का सत्यापन खाते के खोलने या संव्यवहार को निष्पादित करने के पश्चात् युक्ति-युक्त समय के भीतर करेगा ।

- (2) जहां ग्राहक कोई व्यक्ति है, वहां वह उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को शासकीय विधिमान्य दस्तावेज जिसमें उसका स्थायी पता, वर्तमान पता या पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों और अपनी नवीनतम फोटोग्राफ की एक प्रति तथा ऐसे अन्य दस्तावेज जिसके अंतर्गत ग्राहक के व्यापार की प्रकृति भी है और वित्तीय प्रास्थिति से संबंधित दस्तावेज भी हैं जिनकी, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के द्वारा अपेक्षा की जाए, देगा ।
- (3) जहां ग्राहक कोई कंपनी है, वहां वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा :
 - (i) निगमन का प्रमाण पत्र ;
 - (ii) ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ;
 - (iii) निदेशकों के बोर्ड से प्राप्त संकल्प और इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए दिए गए मुख्तारनामों, और
 - (iv) इस निमित्त संव्यवहार के लिए मुख्तारनामा धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (4) जहां ग्राहक कोई भागीदारी फर्म है, वहां वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा :
 - (i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;
 - (ii) भागीदारी विलेख ; और
 - (iii) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (5) जहां ग्राहक कोई न्यास है, वहां वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा :
 - (i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;
 - (ii) न्यास विलेख ; और
 - (iii) उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (6) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यक्तियों का एक निकाय है, वहां वह बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा :
 - (i) ऐसे संगम या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प ;
 - (ii) उसे उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा ;
 - (iii) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ;

- (iv) ऐसे किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सामूहिक रूप से सिद्ध करने के लिए ऐसी अन्य सूचनाएं जो बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित की जा सके ।
- (7) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, ग्राहक पहचान कार्यक्रम को तैयार करेगा और उसका कार्यान्वयन करेगा, जिसमें इस नियम के पूर्वगामी उपनियमों की अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा और ऐसी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन्हें वह ग्राहकों की सही पहचान को निश्चित करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु समुचित समझता है । ग्राहक पहचान कार्यक्रम की एक प्रति निदेशक को भेजी जाएगी ।
10. ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों को रखना-
- (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती अपने ग्राहकों की पहचान के अभिलेख रखेगी ।
- (2) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में हार्ड और सॉफ्ट कॉपियों में रखे जाएंगे ।
- (3) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख, ग्राहक और यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के मध्य संव्यवहार की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे ।
11. निर्वचन -

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[अधिसूचना सं. 9/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules for maintenance of records of the nature and value of transactions, the procedure and manner of maintaining and time for furnishing of information and verification of records of the identity of the clients of the banking companies, financial institutions and intermediaries, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
- (b) "client" means a person that engages in a financial transaction or activity with a banking company, or financial institution or intermediary and includes a person on whose behalf the person that engages in the transaction or activity, is acting;
- (c) "Director" means the Director appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act for the purposes of sections 12 and 13 of the Act;
- (d) "officially valid document" means the passport, the driving licence, the Permanent Account Number (PAN) Card, the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India or any other document as may be required by the banking company, or financial institution or intermediary;
- (e) "prescribed value" means the value of transaction prescribed under these rules;
- (f) "Principal Officer" means an officer designated by a banking company, financial institution and intermediary, as the case may be;
- (g) "suspicious transaction" means a transaction whether or not made in cash which, to a person acting in good faith –
 - (a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve the proceeds of crime; or
 - (b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or
 - (c) appears to have no economic rationale or bonafide purpose;
- (h) "transaction" includes deposit, withdrawal, exchange or transfer of funds in whatever currency, whether in cash or by cheque, payment order or other instruments or by electronic or other non-physical means.

- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Maintenance of records of transactions (nature and value). –

- (1) Every banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, shall maintain a record of, –

- (A) all cash transactions of the value of more than rupees ten lakhs or its equivalent in foreign currency;
- (B) all series of cash transactions integrally connected to each other which have been valued below rupees ten lakhs or its equivalent in foreign currency where such series of transactions have taken place within a month;
- (C) all cash transactions where forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine and where any forgery of a valuable security has taken place;
- (D) all suspicious transactions whether or not made in cash and by way of :
 - (i) deposits and credits, withdrawals into or from any accounts in whatsoever name they are referred to in any currency maintained by way of :
 - (a) cheques including third party cheques, pay orders, demand drafts, cashiers cheques or any other instrument of payment of money including electronic receipts or credits and electronic payments or debits, or
 - (b) travellers cheques, or
 - (c) transfer from one account within the same banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, including from or to Nostro and Vostro accounts, or
 - (d) any other mode in whatsoever name it is referred to;
 - (ii) credits or debits into or from any non-monetary accounts such as d-mat account, security account in any currency maintained by the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be;
 - (iii) money transfer or remittances in favour of own clients or non-clients from India or abroad and to third party beneficiaries in India or abroad including transactions on its own account in any currency by any of the following:-
 - (a) payment orders, or
 - (b) cashiers cheques, or
 - (c) demand drafts, or
 - (d) telegraphic or wire transfers or electronic remittances or transfers, or
 - (e) internet transfers, or

- (f) Automated Clearing House remittances, or
 - (g) lock box driven transfers or remittances, or
 - (h) remittances for credit or loading to electronic cards, or
 - (i) any other mode of money transfer by whatsoever name it is called;
- (iv) loans and advances including credit or loan substitutes, investments and contingent liability by way of:
- (a) subscription to debt instruments such as commercial paper, certificate of deposits, preferential shares, debentures, securitised participation, inter bank participation or any other investments in securities or the like in whatever form and name it is referred to, or
 - (b) purchase and negotiation of bills, cheques and other instruments, or
 - (c) foreign exchange contracts, currency, interest rate and commodity and any other derivative instrument in whatsoever name it is called, or.
 - (d) letters of credit, standby letters of credit, guarantees, comfort letters, solvency certificates and any other instrument for settlement and/or credit support;
- (v) collection services in any currency by way of collection of bills, cheques, instruments or any other mode of collection in whatsoever name it is referred to.

4. Records containing Information – The records referred to in rule 3 shall contain the following information:-

- (a) the nature of the transactions;
- (b) the amount of the transaction and the currency in which it was denominated;
- (c) the date on which the transaction was conducted; and
- (d) the parties to the transaction.

5. Procedure and manner of maintaining information. – (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall maintain information in respect of transactions with its client referred to in rule 3 in hard and soft copies in accordance with the procedure and manner as may be specified by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, from time to time.

- (2) **Every banking company, financial institution and intermediary, shall evolve an internal mechanism for maintaining such information in such form and at such intervals as may be specified by the Reserve Bank of India, or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, from time to time.**
- (3) It shall be the duty of every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, under sub-rule (1).
6. **Retention of records –** The records referred to in rule 3 shall be maintained for a period of ten years from the date of cessation of the transactions between the client and the banking company, financial institution or intermediary, as the case may be.
7. **Procedure and manner of furnishing information. –** (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall communicate the name, designation and address of the Principal Officer to the Director.
- (2) The Principal Officer shall furnish the information referred to in rule 3 to the Director on the basis of information available with the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be. A copy of such information shall be retained by the Principal Officer for the purposes of official record.
- (3) Every banking company, financial institution and intermediary may evolve an internal mechanism for furnishing information referred to in rule 3 in such form and at such intervals as may be directed by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be.
- (4) It shall be the duty of every banking company, financial institution and intermediary to observe the procedure and the manner of furnishing information referred to in rule 3 as specified by the Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India under sub-rule (3), as the case may be.
8. **Furnishing of information to the Director. –** The Principal Officer of a banking company, the financial institution and intermediary, as the case may be, shall furnish the information in respect of transactions referred to in rule 3 every month to the Director by the 7th day of the succeeding month other than transactions referred to in clauses (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3:

Provided that information in respect of transactions referred to in clauses (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3 shall be promptly

furnished in writing or by way of fax or electronic mail to the Director not later than three working days from the date of occurrence of such transactions.

9. **Verification of the records of the identity of clients.** – (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall, at the time of opening an account or executing any transaction with it, verify and maintain the record of identity and current address or addresses including permanent address or addresses of the client, the nature of business of the client and his financial status;

Provided that where it is not possible to verify the identity of the client at the time of opening an account or executing any transaction, the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall verify the identity of the client within a reasonable time after the account has been opened or the transaction has been executed.

- (2) Where the client is an individual, he shall for the purpose of sub-rule (1) submit to the banking company or the financial institution or the intermediary, as the case may be, one certified copy of an officially valid document containing details of his permanent address or addresses, current address or addresses, and one copy of his recent photograph and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the banking company or the financial institution or the intermediary, as the case may be.
- (3) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, three certified copies of the following documents :
- (i) Certificate of incorporation;
 - (ii) Memorandum and Articles of Association;
 - (iii) a resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and
 - (iv) an officially valid document in respect of managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf.
- (4) Where the client is a partnership firm, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company, or the financial institution, or the intermediary three certified copies of the following documents:
- (i) registration certificate;
 - (ii) partnership deed; and

- (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.
- (5) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company, or the financial institution, or the intermediary three certified copies of the following documents:
- (i) registration certificate;
 - (ii) trust deed; and
 - (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.
- (6) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the banking company, or the financial institution or the intermediary three copies of the following documents:
- (i) resolution of the managing body of such association or body of individuals;
 - (ii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;
 - (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf; and
 - (iv) such information as may be required by the banking company or the financial institution or the intermediary to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals.
- (7) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall formulate and implement a client identification programme which shall incorporate the requirements of the foregoing sub-rules of this rule, and such other additional requirements that it considers appropriate to enable it to determine the true identity of its clients. A copy of the client identification programme shall be forwarded to the Director.
- 10. Maintenance of the records of the identity of clients. –** (1) Every banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, shall maintain the records of the identity of its clients.
- (2) The records of the identity of clients shall be maintained in hard and soft copies in a manner as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time.

- (3) The records of the identity of clients shall be maintained for a period of ten years from the date of cessation of the transactions between the client and the banking company or financial institution or intermediary, as the case may be.

11. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

[Notification No. 9/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (ब) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों की प्रति और तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित सामग्री अग्रेषित करने की रीति, तथा व्यक्ति की तलाशी, अभिलेखों को परिबद्ध करने और उनकी अभिरक्षा तथा उनके प्रतिधारण की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) “न्याय निर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकारी” से निदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी अभिप्रेत है, और जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा प्राधिकृत है ;

- (घ) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 48 में विनिर्दिष्ट वर्गों के प्राधिकारियों में से कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;
- (ङ) “अभिहित अधिकारी” से नियम 10 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (च) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए “निदेशक” से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;
- (छ) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए “निदेशक” या “अपर निदेशक” या “संयुक्त निदेशक” या “उप निदेशक” या “सहायक निदेशक” से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक अभिप्रेत है ;
- (ज) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ;
- (झ) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए “परिबंधन प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक अभिप्रेत है ;
- (ञ) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए “सामग्री” से, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात् नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, -
- (i) अनुसूची के भाग क और भाग ख के पैरा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई रिपोर्ट ;
 - (ii) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन किसी अपराध के संबंध में स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए फाइल की गई कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई, परिवाद ;

- (ट) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए “सामग्री” से, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात् नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, -
- (i) अनुसूची के भाग क के पैरा 1 या भाग ख के पैरा 1 या पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 या पैरा 5 के अधीन किसी अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई रिपोर्ट ; या
- (ii) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन किसी अपराध के संबंध में स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए फाइल की गई कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई परिवाद ;
- (ठ) “स्थान” से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां धन शोधन का अपराध कारित करने वाला कार्य किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य स्थान भी है, चाहे वहां कोई क्रियाकलाप किया गया हो अथवा नहीं, जिसमें ऐसा क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि से कार्य (कार्यों) से संबंधित कोई अभिलेख या उसकी संपत्ति का कोई भाग रखा गया है या रखे गए हैं ;
- (ड) “अभिलेखों” के अन्तर्गत पुस्तकों के रूप में या किसी कंप्यूटर में या टेपों या डिस्कों या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे अभिलेख या किसी भी प्रकार की अनुलिपीकृत सूचना, चाहे उसे सामान्य या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त किया गया हो और ऐसे अन्य दस्तावेज भी हैं, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हों ;
- (ढ) “अनुसूची” से अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ण) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।
- (त) “समन करने वाला अधिकारी” से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसको अधिनियम की धारा 50 की पधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति है ।
- (2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. तलाशी लेने से संबंधित प्रक्रिया - (1) निदेशक अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकार इन नियमों से संलग्न प्ररूप (1) में होगा ।

(2) नियम (2) के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा -

(क) किसी ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने या उसकी तलाशी लेने, जिसके संबंध में उसके पास यह संदेह करने के कारण हैं कि वहां अपराध के ऐसे अभिलेख या आगम रखे गए हैं,

(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी दरवाजे, बाक्स, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ने, जिनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करने ;

(घ) ऐसे अभिलेखों को चिह्नंकित करने या उनसे उद्धरण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने या कराने ;

(ङ) ऐसे अभिलेख या संपत्ति का एक नोट या सूची बनाने ;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, ऐसे सभी विषयों की बाबत शपथ पर परीक्षा करने, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों ।

परन्तु अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कोई तलाशी तब तक नहीं की जाएगी जब तक -

(क) अनुसूची के भाग क और भाग ख के पैरा (1) के अधीन अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न की गई हो ; या

(ख) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन किसी अपराध के संबंध में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई पुलिस रिपोर्ट या परिवाद फाइल न किया गया हो ;

(2) तलाशी लेने से पूर्व, प्राधिकारी, -

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, उस बस्ती के, जहां ऐसा भवन या स्थान है, जिसकी तलाशी ली जानी है, दो या अधिक सम्मानित निवासियों को ; और

(ख) जहां किसी जलयान, यान या वायुयान की तलाशी ली जानी है, वहां किन्हीं भी दो या अधिक सम्मानित व्यक्तियों को, तलाशी के दौरान उपस्थित रहने और उसका साक्षी बनने के लिए बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा ।

(4) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या उसमें उपस्थित कोई व्यक्ति, प्राधिकार प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकारी को उसमें अबाध प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी लेने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

(5) यदि ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता तो प्राधिकार का निष्पादन करने वाले प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुलिस अधिकारियों या अधिनियम की धारा 54 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारियों की यथाअपेक्षित सहायता से ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करे और उसकी तलाशी ले और यदि उसके द्वारा अपना प्राधिकार प्रस्तुत किए जाने और प्रवेश करने की मांग सम्यक रूप से किए जाने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसके लिए ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भवन या स्थान के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना भी विधिपूर्ण होगा, चाहे वह स्थान तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का :

परन्तु यदि ऐसा कोई भवन या स्थान ऐसा अपार्टमेंट है, जो किसी ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती तो प्राधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा देगा और तब अपार्टमेंट का ताला तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

(6) यदि किसी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में, जिसकी तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में गतिशील होने या किसी अन्य

कारण से प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो प्राधिकार का निष्पादन करने वाले प्राधिकारी के लिए, पुलिस अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों की, जो अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट हैं, यथा अपेक्षित सहायता से किसी ऐसे जलयान या यान को रोकना या किसी वायुयान की दशा में रुकने और नीचे उतरने के लिए मजबूर करना और जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी लेना विधिपूर्ण होगा और यदि उसके द्वारा अपना प्राधिकार प्रस्तुत किए जाने और प्रवेश करने की मांग सम्यक् रूप से किए जाने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है तो उसके लिए ऐसे जलयान, यान या वायुयान के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना भी विधिपूर्ण होगा, चाहे वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का ;

परन्तु यदि ऐसा कोई जलयान, यान या वायुयान किसी ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो रुढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती तो प्राधिकारी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा देगा और उसके पश्चात् जलयान, यान या वायुयान का दरवाजा तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

(7) प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में स्थित किसी बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या किसी अन्य पात्र का स्वामी है या वे उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में हैं, उसे खोलने और उसकी अंतर्वस्तु की जांच या परीक्षा करने के लिए उस तक पहुंच प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे किसी बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या किसी अन्य पात्र का ताला तोड़ सकेगा जिसे प्राधिकारी निदेशक द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे ।

(8) तलाशी लिए जाने वाले भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसके अन्तर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति भी है, तलाशी के दौरान वहां उपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

4. अभिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया -

(1) प्राधिकारी, किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान की तलाशी के परिणामस्वरूप पाए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है वहां प्राधिकारी, ऐसे स्वामी या व्यक्ति को, जिसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में ऐसा अभिलेख या संपत्ति है, एक से आदेश की तामील कर सकेगा कि वह प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय ऐसे अभिलेख या संपत्ति को नहीं हटाएगा या उसे अपने से दूर नहीं करेगा या उनके संबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं करेगा, ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वह ऐसे उपाय कर सकेगा, जो आवश्यक हों ।

(2) प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप 2 में एक अभिग्रहण ज्ञापन (मदों की सूची) तैयार करेगा जिसे उसे तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसके अन्तर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति भी है, परिदत्त करेगा और प्राधिकारी इस प्रकार तैयार की गई सूची की एक प्रति निदेशक और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ।

(3) प्राधिकारी ऐसी संपत्तियों के, जिनके अन्तर्गत तलाशी के दौरान अभिगृहीत सोना चादी, जेवरात और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ और चीजें भी हैं, अभिलेख एक पैकेज में रखेगा या रखवाएगा जिसमें उसमें रखे सोना चादी, जेवरात और अन्य मूल्यवान वस्तुओं और चीजों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे, ऐसे प्रत्येक पैकेज पर एक पहचान चिन्ह और प्राधिकारी की मुद्रा होगी तथा तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसके अन्तर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति भी है, को भी अपनी मुद्रा लगाने की अनुमति दी जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अनुसार तैयार की गई सूची की एक प्रति तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसके अन्तर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति भी है, परिदत्त की

जाएगी । प्राधिकारी उसकी एक प्रति निदेशक और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों का लागू होना -

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे अधिनियम के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबन्धों से असंगत नहीं हैं ।

6. अभिलेखों का परिबंधन.-

(1) परिबंधन प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध कर सकेगा :

परंतु जहां परिबंधन प्राधिकारी उप निदेशक या सहायक निदेशक है, वहां वह किन्हीं अभिलेखों को लिखित रूप में उसके कारणों को लेखबद्ध किए बिना परिबद्ध नहीं करेगा और तुरंत ऐसे कारणों को निदेशक को अग्रेषित करेगा ।

(2) यदि परिबंधन प्राधिकारी पुलिस या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या दोनों की सहायता की अपेक्षा करता है तो अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन किन्हीं अभिलेखों का परिबंधन करते समय अधिनियम की धारा 54 के अधीन यथा आवश्यक सहायता की मांग करना उसके लिए विधिपूर्ण होगा ।

(3) निदेशक से भिन्न परिबंधन प्राधिकारी परिबद्ध किए गए अभिलेखों की तीन प्रतियों में एक सूची तैयार करेगा । जहां परिबंधन प्राधिकारी निदेशक है, वहां वह ऐसी सूची दो प्रतियों में तैयार करेगा ।

(4) अभिलेखों की किसी सूची का प्रत्येक पृष्ठ परिबंधन प्राधिकारी और उस व्यक्ति द्वारा जिससे अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, हस्ताक्षरित होगा । उस दशा में जहां वह व्यक्ति जिससे अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, हस्ताक्षर करने से इंकार करता है वहां परिबंधन प्राधिकारी उसमें ऐसे इंकार को अभिलिखित करेगा ।

(5) निदेशक से भिन्न परिबंधन प्राधिकारी ऐसी सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा, जिससे अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं और एक प्रति अपने पास रखते हुए तुरंत एक प्रति निदेशक को अग्रेषित करेगा। जहां परिबंधन प्राधिकारी निदेशक है वहां वह ऐसी सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जिससे अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं और एक प्रति अपने पास रखेगा।

(6) निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक से भिन्न परिबंधन प्राधिकारी लिखित रूप में निदेशक का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् इस नियम के अधीन परिबद्ध किए गए किन्हीं अभिलेखों को उस व्यक्ति को वापस कर सकेगा जिससे अभिलेख परिबद्ध किए गए थे यदि ऐसे अभिलेख इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए आगे उपयोगी और सुसंगत नहीं हैं।

7. अभिलेखों की अभिरक्षा.-

अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन परिबंधन प्राधिकारी द्वारा परिबद्ध किए गए किन्हीं अभिलेखों को उसकी अभिरक्षा में रखा जा सकेगा :

परंतु जहां परिबंधन प्राधिकारी उप निदेशक या सहायक निदेशक है वहां वह लिखित रूप में निदेशक का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए ऐसे किन्हीं अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

8. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की प्रति और अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित कारणों और सामग्री की प्रति अग्रेषित करने की रीति -

(1) प्राधिकारी, यथास्थिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों की अपने कब्जे में सामग्री सहित प्रति की एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे कारणों और सामग्री को अग्रेषित करते समय मुहरबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक पत्र भी लिखेगा।

(2) प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे मुहरबंद करने से पूर्व लिफाफे में इन नियमों से संलग्न प्ररूप 3 में एक अभिस्वीकृति-पट्टी रखेगा।

(3) प्राधिकारी, यथास्थिति, मुहरबंद लिफाफे पर अग्रेषण का संदर्भ संख्यांक और प्रेषण की तारीख उपदर्शित करेगा।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर “गोपनीय” और “केवल प्रेषिती द्वारा खोला जाए” चिन्हित किया जाएगा। मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की प्राधिकारिक मुद्रा सहित नाम और उसका पूरा पता वर्णित होंगे।

(5) प्राधिकारी, यथास्थिति, मुहरबंद लिफाफे को एक बाहरी मुहरबंद लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-IV में अभिस्वीकृति-पट्टी रखेगा।

(6) बाहरी लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और “गोपनीय” चिन्हित किया जाएगा। मुहरबंद बाहरी लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता वर्णित होगा।

(7) प्राधिकारी, यथास्थिति, इस नियम के प्रयोजनों के लिए विहित प्ररूप में रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे अभिस्वीकृति-पट्टी रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारणों तथा सामग्री की प्रति भेजे जाने के ठीक पश्चात्, यथाशीघ्र रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

9. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा तलाशी और अभिग्रहण तथा व्यक्ति की तलाशी से संबंधित कारणों और सामग्री की एक प्रति की प्राप्ति की अभिस्वीकृति:-

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय का अभिहित अधिकारी, प्ररूप-IV के साथ बाहरी मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति पर, प्ररूप-IV को सम्यक् रूप से भरके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम स्पष्ट रूप से लिख कर अग्रेषित करेगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर प्ररूप-IV को प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को खोलने पर प्ररूप-III को सम्यक् रूप से भरके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम स्पष्ट रूप से लिख कर अग्रेषित करेगा । प्ररूप III को, प्राधिकारी को अग्रेषित करने से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर कारणों की प्रति और सामग्री की प्राप्ति के टोकन के रूप में लगाई जाएगी ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए, लेखबद्ध किए गए कारणों की प्रति के साथ सामग्री के प्राप्ति के ब्यौरे दर्शित करते हुए, रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे अभिस्वीकृति पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर और रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कारणों और सामग्री के प्राप्त होने के ठीक पश्चात् रजिस्ट्रों में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

10. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा तलाशी और अभिग्रहण और व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित कारणों की प्रति और सामग्री प्रतिधारित करने की अवधि.-

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, तलाशी और अभिग्रहण और व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित कारणों की प्रति और सामग्री को दस वर्ष की अवधि के लिए या, दस वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व प्रतिधारित करेगा यदि -

(i) अधिनियम की धारा 8 के अधीन कोई कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई हैं, तो वहां ऐसी कार्यवाहियों के निपटारे होने तक ; या

(ii) जहां अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपील अधिकरण को कोई अपील की गई है तो वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक ; या

(iii) जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई अपील की गई है तो वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील का निपटारा किए जाने तक, जो भी बाद में हो ।

11. अभिलेखों के प्ररूप - समन करने वाला अधिकारी, अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-V में समन जारी करेगा।

12. निर्वचन.-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उस विषय को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप सं० 1

(नियम 3 का उपनियम (1) देखें)

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण का प्राधिकार

_____ का प्राधिकार सं०
[वर्ष]

तारीख _____

मैं _____, निदेशक यह विश्वास करने का कारण रखता हूँ कि _____
(व्यक्ति का नाम और पूरा पता)

- (i) ने ऐसा कार्य किया है जो धन शोधन को गठित करता है, या
- (ii) के कब्जे में धन शोधन में अंतर्वलित अपराध के आगम हैं, या
- (iii) के कब्जे में धन शोधन से संबंधित अभिलेख हैं, और

नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसर में ऐसे कतिपय दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत अपराध के आगम और / या धन शोधन के अभिलेख भी हैं, छुपाए गए हैं जो मेरी राय में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन अन्वेषण और कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे।

मैं.....को

(प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम और पदनाम)

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की उपधारा (1) और धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण के कारणों और सामग्री, अभिलेखों का परिबंधन और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 के नियम 3 के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों की तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

तारीख _____ को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन दिया गया।

परिसरों की अनुसूची :

(निदेशक)

(हस्ताक्षर मुद्रा सहित)

प्ररूप 2

(नियम 4 का उपनियम (2) देखें)

अभिग्रहण ज्ञापन (मदों की सूची)

तारीख
 बजे से बजे तक
 (समय) (समय)

पंच साक्षी

1.
 (नाम पूरे पते के साथ)
2.
 (नाम पूरे पते के साथ)

हम, ऊपर नामित पंच श्री द्वारा बुलाए जाने पर
 (अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता)
 में उपस्थित हुए हैं। यहां हमें श्री द्वारा
 (परिसरों का पूरा पता) (निदेशक का नाम, पदनाम और पूरा पता)

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 17 के अधीन श्री
 को ऊपर उल्लिखित परिसर की तलाशी लेने
 (निदेशक द्वारा प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता)

और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करने वाला तारीख का प्राधिकार दिखाया गया था। हमने

और साथ ही श्री ने भी प्राधिकार पर, उसे देखे जाने के टोकन के रूप में तारीख के साथ
 (परिसर के अधिभोगी का नाम)

हस्ताक्षर किए। वास्तविक रूप से तलाशी आरंभ करने से पूर्व और तलाशी समाप्त होने के पश्चात् श्री
 ने और उनके साथ उपस्थित अधिकारियों अर्थात्
 (प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता)

सर्वश्री / श्री / श्रीमती ने अपनी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी लिखाने का प्रस्ताव
 किया था, जिसके लिए दोनों मौकों पर हमारी उपस्थिति में सर्वश्री / श्री / श्रीमती
 (परिसर के अधिभोगी)

तारीख को बजे आरंभ हुई थी और तारीख को बजे समाप्त हुई थी।
 तलाशी के परिणामस्वरूप
 (अपराध के आगमों या अभिलेखों को विनिर्दिष्ट करें)

की जांच की गई थी और सत्यापन किया गया था तथा नीचे अनुसूची में दिए गए व्योरे के अनुसार सूची तैयार की गई थी या बरामदगी की गई थी और अभिग्रहण किया गया था। तलाशी शांतिपूर्वक व्यवस्थित रीति से ली गई थी और तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई थी।

(हस्ताक्षर)
प्राधिकारी
(मुद्रा)

अनुसूची
[बरामद किए गए और अभिगृहीत मदों की सूची]

पंच साक्षी

1.

[तारीख सहित हस्ताक्षर]

2.

[तारीख सहित हस्ताक्षर]

[तलाशी लिए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर]

(प्रति प्राप्त की)

(प्राधिकारी)
हस्ताक्षर, मुद्रा सहित

[तलाशी लिए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर]

टिप्पण : अभिग्रहण ज्ञापन के प्रत्येक पृष्ठ पर, पंच साक्षियों, तलाशी लिए गए व्यक्ति और प्राधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाने हैं।

प्रारूप 3
(नियम 8 का उपनियम (2) देखें)

अभिस्वीकृति पत्र

क्रम सं० —————

..... (प्राधिकारी का नाम) से तारीख को (समय) बजे

पत्र सं० तारीख को, कारणों और सामग्री के साथ एक प्रति पृष्ठ सं० ———

से ——— तक प्राप्त हुई।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख

.....

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

.....

[प्राधिकारी का नाम और पदनाम]

पता -----

प्ररूप 4

(नियम 8 का सपनियम (5) देखें)

अभिस्वीकृति पर्ची

क्रम सं० -----

(प्राधिकारी का पदनाम) से (तारीख) को (समय) बजे

मुहरबंद लिफाफा, जिसकी संख्या, तारीख है, प्राप्त हुआ।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के

कार्यालय के अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर]

.....

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के

कार्यालय के अभिहित अधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

.....

[प्राधिकारी का नाम और पदनाम]

पता -----

प्ररूप 5
(नियम 11 देखें)

समन करने के लिए प्ररूप

.....
.....
.....
(समन करने वाले अधिकारी का पता)

सं०

मैं.....निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के उपबन्धों के अधीन अन्वेषण कर रहा हूँ ।

और मैं, की उपस्थिति उक्त अन्वेषणों के संबंध में
(समन किए गए व्यक्ति का नाम और पता)

आवश्यक समझता हूँ ।

अतः, अब मैं, उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त

(समन किए गए व्यक्ति का नाम और पता)

की हाजिरी नीचे सारणी के अनुसार दस्तावेजों सहित मेरे कार्यालय में तारीख —————को —————बजे अपेक्षित समझता हूँ ।

अनुसूची

तारीख ————— को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन दिया गया ।

समन करने वाला अधिकारी
(नाम और पूरा पता)
(मुद्रा)

सेवा में

.....
(समन किए गए व्यक्ति का नाम और उसका पता)

टिप्पण :

1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आप अनुसूची में यथावर्णित साक्ष्य देने में असफल रहते हैं तो आप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन दंडिक कार्यवाहियों के लिए दायी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 10/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a), clause (m), clause (n), clause (o) and clause (w) of sub-section (2), of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the Forms, search and seizure and the manner of forwarding a copy of the reasons and the material relating to search and seizure and search of person to the Adjudicating Authority, impounding and custody of records and the period of retention thereof, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
 - (a) “Act” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) “Adjudicating Authority” means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
 - (c) “authority” for the purposes of sub-section (2) of section 17 of the Act means an officer subordinate to the Director and authorised by the Director under sub-section (1) of section 17 of the Act;
 - (d) “authority” for the purposes of sub-section (1) of section 18 of the Act means an authority from among the classes of authorities specified in section 48 of the Act, authorized by the Central Government by general or special order;
 - (e) “designated officer” means the officer designated by the Adjudicating Authority for the purpose of sub-rule (1) of rule 10;

- (f) "Director" for the purpose of sub-section (1) of section 17 of the Act means the Director appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act;
- (g) "Director" or "Additional Director" or "Joint Director" or "Deputy Director" or "Assistant Director" for the purpose of sub-section (5) of section 50 of the Act, means a Director or Additional Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49 of the Act;
- (h) "Form" means forms appended to these rules;
- (i) "impounding authority" for the purpose of sub-section (5) of section 50 of the Act, means the Director or Additional Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49 of the Act;
- (j) "material" for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the Act means the material in possession of the authority referred to in clause (d) of sub-rule (1) of rule 2, after search and seizure, under sub-section (1) of section 17 of the Act, including –
 - (i) a report forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A and Part B of the Schedule; or
 - (ii) a police report or a complaint filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section(1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) in relation to an offence under paragraph 2 of Part A of the Schedule;
- (k) "material" for the purpose of sub-section (2) of section 18 of the Act means the material in possession of the authority referred to in clause (e) of sub-rule (1) of rule 2, after search and seizure, under sub-section (1) of section 18 of the Act, including –
 - (i) a report forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A or paragraph 1 or paragraph 2 or paragraph 3 or paragraph 4 or paragraph 5 of Part B of the Schedule; or

- (ii) a police report or a complaint filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section(1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) in relation to an offence under paragraph 2 of Part A of the Schedule;
 - (l) "place" means a place, where an act which constitutes the commission of the offence of money-laundering is carried on and includes any other place, whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are or is kept;
 - (m) "records" include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information of any type whether expressed in ordinary or machine language and such other documents as may be useful for the purposes of these rules;
 - (n) "Schedule" means the Schedule to the Act;
 - (o) "section" means a section of the Act.
 - (p) "Summoning Officer" means an officer who has the power to summon any person under sub-section (2) of section 50 of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure relating to search.** – (1) The Director may authorize any officer subordinate to him for the purposes of sub-section (1) of section 17 of the Act and such authorization shall be in Form I appended to these rules.

- (2) The authority referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 2, shall be empowered to –
- (a) enter and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept;
 - (b) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clause(a) where the keys thereof are not available;
 - (c) seize any record or property found as a result of such search;

- (d) place marks of identification on such record or make or cause to be made extracts or copies therefrom;
- (e) make a note or an inventory of such record or property;
- (f) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Act.

Provided that no search under sub-section (1) of section 17 of the Act shall be conducted, unless -

- (a) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A and Part B of the Schedule, a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been forwarded to a Magistrate; or
 - (b) in relation to an offence under paragraph 2 of Part A of the Schedule, a police report or a complaint has been filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section(1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
- (3) Before making a search, the authority, shall-
- (a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable persons of that locality in which the building or place to be searched is situated; and
 - (b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.
- (4) Any person in charge of, or, in any building, place, vessel, vehicle or aircraft shall, on production of the authorisation, allow the authority free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein.
- (5) If ingress into such building or place cannot be obtained, it shall be lawful for the authority executing the authorisation, with such assistance of police officers or of such other officers as specified in section 54 of the Act, as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any lock of any door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the authority shall before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it.

- (6) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorized to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for the authority executing the authorisation, with such assistance as may be required of police officers and such officers, as specified in section 54 of the Act, to stop any such vessel or vehicle or in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft, and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft to break open any door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of the authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance :

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the authority shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the door of any vessel, vehicle or aircraft and enter it.

- (7) The authority may require any person who, is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situated in such building, place, vessel, vehicle or aircraft, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may break open the lock of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which the authority may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified by the Director in this behalf.
- (8) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search.

4. **Procedure relating to seizure.** — (1) The authority may seize any record or property found as a result of search of any building, place, vessel, vehicle or aircraft:

Provided that where it is not practicable to seize any record or property, the authority may serve an order on the owner or the person who is in immediate possession or control of any such record

of property that he shall not remove, part with or otherwise deal with it except with the previous permission of the authority, who may take such steps as may be necessary for ensuring such compliance.

- (2) The authority shall prepare a seizure memo (inventory of items) in Form II appended to these rules which shall be delivered to the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf and the authority shall also forward a copy of the inventory so prepared to the Director and the Adjudicating Authority.
 - (3) The authority shall place or cause to be placed the records of properties including bullion, jewellery and other valuable articles and things seized during the search in a package which shall contain the details of the bullion, jewellery and other valuable article and things placed therein, such packages shall bear an identification mark and the seal of the authority, and the occupant of such building, place, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft searched or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal on packages.
 - (4) A copy of the list prepared in accordance with sub-rule (3) shall be delivered to the occupant of the building, place, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft searched or any other person on his behalf and the authority shall also forward a copy thereof to the Director and the Adjudicating Authority.
5. **Applicability of the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.** — The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act relating to search and seizure.
6. **Impounding of records.** — (1) The impounding authority may impound any records produced before him in any proceedings under the Act :
- Provided** that where the impounding authority is a Deputy Director or an Assistant Director, he shall not impound any records without recording his reasons in writing, and shall immediately forward such reasons to the Director.
- (2) If the impounding authority requires assistance of police or officers of the Central Government, or both, it shall be lawful for him to seek such assistance as necessary under section 54 of the Act while impounding any records under sub-section (5) of section 50 of the Act.
 - (3) The impounding authority, other than the Director, shall prepare an inventory of impounded records in triplicate. Where the impounding authority is the Director, he shall prepare such inventory in duplicate.
 - (4) Each page of an inventory of records shall be signed by the impounding authority and the person from whom records have been

impounded. In case where the person from whom records have been impounded refuses to sign, the impounding authority shall record such refusal therein.

- (5) The impounding authority other than the Director shall give one copy of such inventory to the person from whom records have been impounded and shall forward immediately one copy to the Director while retaining one copy with him. Where the impounding authority is the Director, he shall give one copy of such inventory to the person from whom records have been impounded and shall retain one copy with him.
- (6) The impounding authority other than the Director may, after obtaining the previous approval of the Director in writing, return any records impounded under this rule, to the person from whom records were impounded if such records are no longer useful and relevant for any proceedings under this Act.

7. Custody of records. – Any records impounded by the impounding authority under sub-section (5) of section 50 of the Act may be retained in his custody:

Provided that where the impounding authority is a Deputy Director or an Assistant Director he shall not retain in his custody any such records for a period exceeding three months, without obtaining the previous approval of the Director in writing.

- 8. Manner of forwarding of a copy of the reasons and the material relating to search and seizure under sub-section (2) of section 17 of the Act and search of persons under sub-section (2) of section 18 of the Act to the Adjudicating Authority. –** (1) The authority, as the case may be, shall prepare an index of a copy of the reasons recorded along with the material in his possession and sign each page of such index and shall also write a letter while forwarding copy of reasons and material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.
- (2) The authority, as the case may be, shall place an acknowledgement slip in Form-III appended to these rules inside the envelope before sealing it.
 - (3) The authority, as the case may be, shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.
 - (4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only" and the complete address of the Adjudicating Authority including his name shall be mentioned on the sealed envelope with official seal.
 - (5) The authority, as the case may be, shall place the sealed envelope inside the outer envelope, and shall place an acknowledgement slip in Form-IV appended to these rules.

- (6) The outer envelope shall be sealed and marked "Confidential". Complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.
- (7) The authority, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material are forwarded to the Adjudicating Authority.
9. **Acknowledgement of receipt of a copy of the reasons and the material relating to search and seizure and search of person by the Adjudicating Authority.** – (1) On receipt of the outer sealed envelope along with Form-IV, the Adjudicating Authority or in his absence, the designated officer of the office of Adjudicating Authority shall forward Form-IV duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding Form-IV to the authority as a token of receipt of the sealed envelope.
- (2) The Adjudicating Authority shall, on opening of the sealed envelope, forward Form-III duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding of Form-III to the authority as a token of receipt of a copy of the reasons and the material.
- (3) The Adjudicating Authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register and register showing details of receipt of a copy of the reasons recorded along with the material for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately on receipt of such copy of the reasons and the material.
10. **Period of retention of copy of the reasons and the material relating to search and seizure and search of persons by the Adjudicating Authority.** – (1) The Adjudicating Authority shall retain copy of the reasons and the material relating to search and seizure and search of persons for a period of ten years or if, before the expiry of the said period of ten years, –
- (i) any proceedings under section 8 of the Act have been commenced, until the disposal of such proceedings, or
- (ii) where an appeal has been preferred to the Appellate Tribunal under section 26 of the Act, until the disposal of such appeal by the Appellate Tribunal, or
- (iii) where an appeal has been filed in the High Court under section 42 of the Act, until the disposal of such appeal by the High Court;
- whichever is later.

11. **Forms of records.** – The Summoning Officer shall, while exercising powers under sub-sections (2) and (3) of section 50, of the Act, issue summons in Form-V appended to these rules.
12. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM I

[See sub-rule (1) of rule 3]

AUTHORISATION FOR SEARCH AND SEIZURE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 17 OF THE ACT

Authorisation Number ... of Dated
[year]

WHEREAS I, Director, have reason to believe that

[name and complete address of the person]

- (i) has committed an act which constitutes money-laundering, or
- (ii) is in possession of proceeds of crime involved in money-laundering, or
- (iii) is in possession of records relating to money-laundering, and

certain documents including proceeds of crime and/or records relating to money-laundering, which in my opinion, will be useful for or relevant to the investigation and proceedings under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) are secreted in the premises specified in the Schedule below.

I hereby authorise

[Name and designation of the authority]

to conduct the search and seizure of the premises specified in Schedule below, under sub-section (1) of section 17 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and rule 3 of the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005.

Given under my hand and seal this day of two thousand

Schedule of premises :

[Director]

[Signature with Seal]

FORM II

[See sub-rule (2) of rule 4]

SEIZURE MEMO (INVENTORY OF ITEMS)

Dated

From to
[time] [time]Panch Witnesses:

1.
[name with complete address]
2.
[name with complete address]

We, the above named panchas having been called upon by Shri
.....
[name, designation and complete address of Officer]
have presented ourselves at.....
.....
[complete address of the premises]

Here we were shown an authorisation dated issued by Shri
..... under section 17 of the
[name, designation and complete address of the Director]
Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) authorising Shri
..... to conduct search
[name, designation and complete address of the officer authorized by the Director]
and seizure of the above mentioned premises. We as well as Shri
..... put our dated signatures on the
[name of the occupier of the premises]

authorisation in token of having seen the same. Before the actual start of search
and after the conclusion of search by Shri
[name, designation and complete address of the authority]
and the accompanying officers viz Sarvashri/Shri/Shrimati.....
..... offered
their personal search which was declined/taken by
Sarvashri/Shri/Shrimati.....

[the occupier of the premises]
on both the occasions in our presence. The search started at
.....hours on and concluded athours
on.....As a result of search
.....were checked and
[specify proceeds of crime or records]

verified and inventory prepared or recovered and seized as per details given in the Schedule below. The search was conducted in a peaceful and orderly manner and no damage to the person or property was caused during the course of search.

[Signature]
Authority

[Seal]

SCHEDULE

[Inventory of items recovered and seized]

Panch Witnesses:

1.
[signature with date]
2.
[signature with date]

.....
[signature of the person searched]

(Authority)
Signature with Seal

(Received copy)
[signature of the person searched]

NOTE :-

Each page of the seizure memo is to be signed and dated by the Panch Witnesses, the person searched and the Authority.

FORM-III

[See sub-rule (2) of rule 8]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a copy of the letter bearing Number..... dated
..... along with the reasons and the material containing
pages..... from..... on..... at.....
[designation of the authority] [date] [time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....
[Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To
[Name and designation of the authority]

Address _____

FORM-IV

[See sub-rule (5) of rule 8]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a sealed envelope bearing number.....

Dated..... from
[designation of the authority]on at.....
[date] [time]Signature of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority......
Name of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority.

To

[Office seal)]

[Name and designation of the authority]Address _____

_____**FORM V**

[See rule 11]

FORM FOR SUMMONS.....
.....
.....

[ADDRESS OF THE SUMMONING OFFICER]

No.

WHEREAS I Director or
Additional Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, am
making investigation under the provisions of the Prevention of Money-laundering
Act, 2002 (15 of 2003).

AND WHEREAS, I consider the attendance of
 necessary in connection with the
 [name of the person summoned and his address]
 said investigations.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon me under
 sub-section (2) and sub-section (3) of section 50 of the said Act, I require the said

 [name of the person summoned and his address]
 to appear before me at my office on at alongwith the
 documents as per schedule below:-

SCHEDULE

Given under my hand and seal this day of two
 thousand

Summoning Officer

[Name and complete address]

[Seal]

To

.....

[Name of the person summoned and his address]

Note:

1. Every proceeding under sub-section (2) and sub-section (3) of section 50 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
2. Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, if you fail to give evidence as mentioned in the schedule, you shall be liable to penal proceedings under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003).

[Notification No. 10/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

स.क.नि. 446(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (त) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री के अग्रेषित करने के प्रारूप और उसकी रीति और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उसके प्रतिधारण की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री अग्रेषित करने की रीति और उसके प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2993 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) “न्याय निर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) “गिरफ्तार करने वाला अधिकारी” से अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “अभिहित अधिकारी” से नियम 4 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) “निदेशक” या “उपनिदेशक” या “सहायक निदेशक” से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, निदेशक या उपनिदेशक या सहायक निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) “प्रारूप” से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(छ) “सामग्री” से यथास्थिति, निदेशक या उपनिदेशक या सहायक निदेशक या किसी प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में की कोई ऐसी सूचना या सामग्री अभिप्रेत है जिसके आधार पर उसने अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कारण अभिलिखित किए हैं ;

(ज) “आदेश” से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी गिरफ्तारी के आधार भी सम्मिलित हैं ;

(झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री अग्रेषित करने की रीति.-

(1) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आदेश की प्रति और कब्जे में की सामग्री की अनुक्रमणिका तैयार करेगा और आदेश और सामग्री की ऐसी अनुक्रमणिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसी अनुक्रमणिका, आदेश और सामग्री न्यायनिर्णायक अधिकारी को मुहरबंद लिफाफे में भेजते समय, एक पत्र भी लिखेगा ।

(2) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी लिफाफे को मुहरबंद करने से पूर्व उसके अंदर इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप-1 में अभिस्वीकृति पर्वी रखेगा ।

(3) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी मुहरबंद लिफाफे पर संदर्भ संख्या और उसे भेजने की तारीख उपदर्शित करेगा ।

(4) मुहरबंद लिफाफे पर “गोपनीय” और “केवल प्रेषिती द्वारा ही खोला जाए” अंकित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के नाम सहित उसका पूरा पता वर्णित होगा । प्राधिकारी मुहरबंद लिफाफे पर अपनी शासकीय मुहर लगाएगा ।

(5) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी मुहरबंद लिफाफे को एक बाहरी लिफाफे में रखेगा और इन नियमों से संलग्न प्रारूप-2 में अभिस्वीकृति पर्वी रखेगा ।

(6) बाहरी लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा । मुहरबंद बाहरी लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता वर्णित होगा ।

(7) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी इस नियम के प्रयोजन के लिए रजिस्टर और अभिस्वीकृति पर्वी रजिस्टर, डाक रजिस्टर जैसे अन्य अभिलेख रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे रजिस्टर में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश की प्रति तथा सामग्री भेजे जाने के ठीक बाद आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

4. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री की प्राप्ति की अभिस्वीकृति.-

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय का

अभिहित अधिकारी, प्ररूप-2 के साथ बाहरी मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति पर, प्ररूप-2 को, उसे सम्यक् रूप से भरने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा उसके हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम स्पष्ट रूप में लिख देने के पश्चात् भेजेगा। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को प्ररूप-2 भेजे जाने से पूर्व मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति के टोकन के रूप में उस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर लगाई जाएगी।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को खोलने के बाद प्ररूप-1 को, उसे सम्यक् रूप से भरने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप में अपना नाम लिखने के पश्चात् भेजेगा। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री की प्राप्ति के रूप में प्ररूप-1 भेजने से पूर्व गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री की प्राप्ति के टोकन के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की उस पर मुहर लगाई जाएगी।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे अभिलेखीकृत पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा और उसमें सामग्री के साथ गिरफ्तारी के आदेश की प्रति का ब्यौरा दर्शित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रजिस्टर में ऐसे ³⁻¹⁻²¹ और सामग्री की प्राप्ति के ठीक पश्चात्, आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री प्रतिधारण की अवधि.-

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री, दस वर्ष की अवधि के लिए प्रतिधारित करेगा या, यदि दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व—

(i) जहां अधिनियम की धारा 8 के अधीन कोई कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई है, तो वहां ऐसी कार्यवाहियों के निपटान तक प्रतिधारित करेगा, या

(ii) जहां अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपील अधिकरण को कोई अपील की गई है तो वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील के निपटान तक प्रतिधारित करेगा, या

(iii) जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई अपील फाइल की गई है तो वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील के निपटान तक प्रतिधारित करेगा,

इसमें जो भी बाद की हो।

6. अभिलेख के प्ररूप.-

गिरफ्तार करने वाला अधिकारी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय इन नियमों से संलग्न प्ररूप-3 में गिरफ्तारी आदेश पर हस्ताक्षर करेगा।

7. निर्वचन.-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप-1**[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]****अभिस्वीकृति पर्ची**

क्रम संख्यांक

निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी से (तारीख) को
 (समय) बजे (गिरफ्तार व्यक्ति का नाम) की
 गिरफ्तारी आदेश की एक प्रति जिसकी सख्या, तारीख है, प्राप्त हुई।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

.....

[गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी]

पता

.....

.....

प्रारूप-2

[नियम 3 का उपनियम (5) देखिए]

अभिस्वीकृति पर्ची

क्रम संख्यांक

निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी से (तारीख) को

..... (समय) बजे मुहर बंद लिफाफा, जिसकी संख्या, तारीख

है, प्राप्त हुआ।

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी / न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर]

.....

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी / न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
कार्यालय के अभिहित अधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

.....

[गिरफ्तार करने वाला अधिकारी]

पता

.....

.....

प्ररूप-3

(नियम 6 देखिए)

गिरफ्तारी आदेश का प्ररूप

मैं निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/केंद्रीय सरकार द्वारा
इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि

(गिरफ्तार व्यक्ति का नाम) निवासी धन-शोधन
निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी रहा है।

अतः, अब मैं धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 19 की उपधारा (1) के
अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त (गिरफ्तार व्यक्ति
का नाम) से पर बजे गिरफ्तार करता हूँ और उसे ऐसी गिरफ्तारी के
आधारों की सूचना दे दी गई है।

तारीख मास दो हजार

गिरफ्तार करने वाला अधिकारी

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

प्रेषिणी

.....

.....

(गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पूरा पता)

[अधिसूचना सं. 11/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a), clause (p) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the Forms, the manner of forwarding a copy of the order of arrest of a person along with the material to the Adjudicating Authority and the period of retention thereof by the Adjudicating Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Forms and the Manner of Forwarding a Copy of Order of Arrest of a Person along with the Material to the Adjudicating Authority and its period of Retention) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
 - (a) “Act” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) “Adjudicating Authority” means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
 - (c) “Arresting Officer” means the Director, Deputy Director, Assistant Director or any other officer, authorized in this behalf by the Central Government by general or special order to exercise the power to arrest any person under sub-section (1) of section 19 of the Act;
 - (d) “designated officer” means the officer designated by the Adjudicating Authority for the purpose of sub-rule(1) of rule 4;
 - (e) “Director” or “Deputy Director” or “Assistant Director” means a Director or a Deputy Director or an Assistant Director, as the case may be, appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act;
 - (f) “Form” means forms appended to these rules;
 - (g) “material” means any information or material in the possession of the Director or Deputy Director or Assistant Director or any authorised officer, as the case may be, on the basis of which he has recorded reasons under sub-section (1) of section 19 of the Act;

(h) "order" means the order of arrest of a person and includes the grounds for such arrest under sub-section (1) of section 19 of the Act;

(i) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of forwarding a copy of the order of arrest and the material to the Adjudicating Authority. –

(1) The Arresting Officer shall prepare an index of the copy of the order and the material in possession and sign each page of such index of the copy of the order and the material and shall also write a letter while forwarding such index, order and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.

(2) The Arresting Officer shall place an acknowledgement slip in Form-I appended to these rules inside the envelope before sealing it.

(3) The Arresting Officer shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.

(4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name shall be mentioned on the sealed envelope with the official seal.

(5) The Arresting Officer shall place the sealed envelope inside an outer envelope, along with an acknowledgement slip in Form-II appended to these rules.

(6) The outer envelope shall be sealed and complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.

(7) The Arresting Officer shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon the copy of the order and the material are forwarded to the Adjudicating Authority.

4. Acknowledgement of receipt of the copy of the order of arrest and the material by the Adjudicating Authority. –

(1) On receipt of the outer sealed envelope along with Form-II, the Adjudicating Authority or in his absence, the designated officer of the office of Adjudicating Authority shall forward Form-II duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding the Form-II to the Arresting Officer as a token of receipt of the sealed envelope.

- (2) The Adjudicating Authority shall, on opening of the sealed envelope, forward Form-I duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding the Form-I to the Arresting Officer as a token of receipt of the copy of order of the arrest and the material.
- (3) The Adjudicating Authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register, and register showing details of receipt of the copy of the order of the arrest along with the material for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the registers immediately on receipt of such order and the material.
5. **Period of retention of a copy of the order of arrest and the material by the Adjudicating Authority.** – The Adjudicating Authority shall retain the copy of order of the arrest and the material for a period of ten years, or, if before the expiry of the said period of ten years, –
- (i) any proceedings under section 8 of the Act have been commenced, until the disposal of such proceedings; or
 - (ii) where an appeal has been preferred to the Appellate Tribunal under section 26 of the Act, until the disposal of such appeal by the Appellate Tribunal; or
 - (iii) where an appeal has been filed in the High Court under section 42 of the Act, until the disposal of such appeal by the High Court;
- Whichever is later.
6. **Forms of records.**– The Arresting Officer while exercising powers under sub-section (1) of Section 19 of the Act shall sign the Arrest Order in Form-III appended to these Rules.
7. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM-I

[See sub-rule (2) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a copy of the order of arrest of.....

[Name of the person arrested]

bearing No.dated

from the Director/Deputy Director/Assistant Director/authorized officer on
 at
 [date] [time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

.....
 [Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To

 [Arresting Officer]

Address : _____

FORM-II

[See sub-rule (5) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a sealed envelope bearing No. dated.....
 from the Director/Deputy Director/Assistant Director/authorized officer on
 at.....
 [date] [time]

Signature of the Adjudicating
 Authority/designated officer
 of the office of Adjudicating
 Authority.

.....
 Name of the Adjudicating
 Authority/designated officer
 of the office of Adjudicating
 Authority.
 [Office seal)]

To

 [Arresting Officer]

Address : _____

FORM III

[See rule 6]

ARREST ORDER

WHEREAS, I Director/Deputy Director/ Assistant Director/Officer authorised in this behalf by the Central Government, have reason to believe that..... resident of
[name of the person arrested]

has been guilty of an offence punishable under the provisions of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (1) of section 19 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), I hereby arrest the said
[name of the person arrested]

at..... hours on and he has been informed of the grounds for such arrest.

Dated at on this day of Two thousand

Arresting Officer
[Signature with Seal]

To

.....
.....

[Name and complete address of the person arrested]

[Notification No. 11/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

स.का.नि. 447(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 20 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति तथा सामग्री के अग्रेषण की रीति और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा प्रतिधारण की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति तथा सामग्री के अग्रेषण की रीति और प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) “न्याय निर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) “प्राधिकृत अधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;
- (घ) “अभिहित अधिकारी” से नियम 4 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (च) “सामग्री” से प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में की कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसके आधार पर उसने अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन कारण लेखबद्ध किए हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—
 - (i) अनुसूची के भाग क के पैरा 1 या भाग ख के पैरा 1 या पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 या पैरा 5 के अधीन अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित रिपोर्ट ; या
 - (ii) अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन अपराध के संबंध में स्थापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन न्याय विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किए जाने के लिए फाइल की गई पुलिस रिपोर्ट या परिवाद ;
- (छ) “आदेश” से न्याय निर्णयन के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के प्रतिधारण का आदेश अभिप्रेत है ;
- (ज) “अभिगृहीत संपत्ति” से अधिनियम की धारा 17 या धारा 18 के अधीन कोई अभिगृहीत संपत्ति अभिप्रेत है ;
- (झ) “अनुसूची” से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ञ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में क्रमशः हैं ।

3. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सामग्री सहित अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रि भेजे जाने की रीति - (1) प्राधिकृत अधिकारी अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति और सामग्री की अनुक्रमणिका तैयार करेगा और आदेश की प्रति तथा सामग्री की ऐसी अनुक्रमणिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और वह आदेश की प्रति तथा सामग्री की ऐसी अनुक्रमणिका न्यायनिर्णायक अधिकारी को मुहरबंद लिफाफे में भेजते समय, एक पत्र भी लिखेगा ।

- (2) प्राधिकृत अधिकारी उक्त लिफाफे को मुहरबंद करने से पूर्व उसके अंदर इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप- I में अभिस्वीकृति-पर्ची रखेगा ।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद लिफाफे पर संदर्भ संख्या और उसे भेजने की तारीख उपदर्शित करेगा ।
- (4) मुहरबंद लिफाफे पर “गोपनीय” और “केवल प्रेषिणी द्वारा ही खोला जाए”, अंकित किया जाएगा । मुहरबंद लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के नाम सहित उसका पूरा पता वर्णित होगा । प्राधिकारी मुहरबंद लिफाफे पर अपनी मुहर लगाएगा ।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद लिफाफे को एक बाहरी लिफाफे में इन नियमों से संलग्न प्ररूप- II में अभिस्वीकृति-पर्ची सहित रखेगा ।
- (6) बाहरी लिफाफे को मुहरबंद किया जाएगा और मुहरबंद बाहरी लिफाफे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूरा पता वर्णित होगा ।
- (7) प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए विहित प्ररूप में रजिस्टर और अभिस्वीकृति-पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर जैसे अन्य ऐसे अभिलेख रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे रजिस्टर में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश की प्रति तथा सामग्री भेजे जाने के ठीक बाद आवश्यक प्रविष्टियां कर दी जाती हैं ।

4. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति और सामग्री की प्राप्ति की अभिस्वीकृति—

- (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय का अभिहित अधिकारी, प्ररूप-III के साथ बाहरी मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति पर, प्ररूप-III को सम्यक् रूप से भरने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा उसके हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम स्पष्ट रूप में लिख देने के पश्चात् भेजेगा । प्राधिकृत प्राधिकारी को प्ररूप-III भेजे जाने से पूर्व मुहरबंद लिफाफे की प्राप्ति के टोकन के रूप में उसपर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की मुहर लगाई जाएगी ।
- (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, मुहरबंद लिफाफे को खोलने के बाद प्ररूप-II को, उसे सम्यक् रूप से भरने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप में अपना नाम लिखने के पश्चात् भेजेगा । प्राधिकृत प्राधिकारी को प्ररूप-II भेजने से पूर्व अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेशों की प्रति और सामग्री की प्राप्ति के टोकन के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कार्यालय की उस पर मुहर लगाई जाएगी ।
- (3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए सामग्री सहित प्रतिधारण आदेश की प्रति की प्राप्ति की बाबत प्राप्ति के विवरण को दर्शाने वाला रजिस्टर और अन्य अभिलेख जैसे अभिस्वीकृति पर्ची, डाक रजिस्टर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रजिस्टर में ऐसे आदेश की प्रति और सामग्री की प्राप्ति के ठीक पश्चात् आवश्यक प्रविष्टियां कर दी जाती हैं ।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा प्रतिधारण के आदेश की प्रति और सामग्री रखे जाने की अवधि— न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की प्रति और सामग्री दस वर्ष की अवधि के लिए रखेगा या, यदि दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व—

- (i) जहां अधिनियम की धारा 8 के अधीन कोई कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई हैं, तो वहां ऐसी कार्यवाहियों के निपटान तक रखेगा, या
- (ii) जहां अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपील अधिकरण को कोई अपील की गई है तो वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील के निपटान तक रखेगा, या
- (iii) जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई अपील की गई है तो वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील के निपटान तक रखेगा ।

इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ति हो..।

6. निर्वचन--

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्रारूप-II

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

अभिस्वीकृति पत्र

क्रम संख्यांक.....

..... [उस प्राधिकृत प्राधिकारी का पदनाम] से (तारीख) को(समय) बजे अभिगृहीत संपत्ति के प्रतिधारण के आदेश की एक प्रति और सामग्री जिसकी संख्या, तारीख है, प्राप्त हुई ।

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

तारीख :

.....
[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

.....

[प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम]

पता

.....

.....

प्रारूप-III

[नियम 3 का उपनियम (5) देखिए]

अभिस्वीकृति पर्ची

क्रम संख्यांक.....

..... [उस प्राधिकृत प्राधिकारी का पदनाम] से (तारीख) को
(समय) बजे मुहरबंद लिफाफा, जिसकी संख्या....., तारीख.....
 (समय)..... है, प्राप्त हुआ।

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
 कार्यालय के अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर]

[न्यायनिर्णायक प्राधिकारी/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के
 कार्यालय के अभिहित अधिकारी का नाम]

[कार्यालय की मुहर]

प्रेषिती

[प्राधिकारी का पदनाम]

पता

.....

.....

[अभिस्वीकृति सं. 12/2005/फा. सं. 6/2/20054-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 73 read with sub-section (2) of section 20 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the manner of forwarding a copy of the order of retention of seized property along with the material to the Adjudicating Authority and its period of retention by the Adjudicating Authority, namely:-

- 1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (the Manner of Forwarding a Copy of the Order of Retention of Seized Property along with the Material to the Adjudicating Authority and the period of its Retention) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
 - (a) “Act” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) “Adjudicating Authority” means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
 - (c) “authorised officer” means an officer authorised by the Director under sub-section (1) of section 20 of the Act;
 - (d) “designated officer” means an officer designated by the Adjudicating Authority for the purpose of sub-rule (1) of rule 4;
 - (e) “Form” means Forms appended to these rules;
 - (f) “material” means any material in the possession of the authorized officer on the basis of which he has recorded reasons under sub-section (1) of section 20 of the Act including –
 - (i) a report forwarded to the Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in relation to an offence under paragraph 1 of Part A, or paragraph 1 or paragraph 2 or paragraph 3 or paragraph 4 or paragraph 5 of Part B, of the Schedule; or
 - (ii) a police report or a complaint filed for taking cognizance of an offence by the Special Court constituted under sub-section (1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (61 of 1985) in relation to an offence under paragraph 2 of Part A of the Schedule;

- (g) "order" means the order for retention of the property for the purposes of adjudication;
 - (h) "seized property" means any property seized under section 17 or section 18 of the Act;
 - (i) "Schedule" means the Schedule to the Act;
 - (j) "section" means a section of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of forwarding the copy of the order of retention of seized property along with the material to the Adjudicating Authority. – (1)

- The authorised officer shall prepare the index of the copy of the order of retention of the seized property and the material and sign each page of such index of the copy of the order and the material and shall also write a letter while forwarding such index of the copy of the order and the material to the Adjudicating Authority in a sealed envelope.
- (2) The authorised officer shall place an acknowledgement slip in Form-I appended to these rules inside the envelope before sealing it.
 - (3) The authorised officer shall indicate a reference number and date of despatch on the sealed envelope.
 - (4) The sealed envelope shall be marked "Confidential" and "To be opened by the addressee only", the complete address of the Adjudicating Authority including his name shall be mentioned on the sealed envelope, with official seal.
 - (5) The authorised officer shall place the sealed envelope inside an outer envelope, along with an acknowledgement slip in Form-II appended to these rules.
 - (6) The outer envelope shall be sealed and complete address of the Adjudicating Authority shall be mentioned on the sealed outer envelope.
 - (7) The authorised officer shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as the copy of the order and the material are forwarded to the Adjudicating Authority.

4. Acknowledgement of receipt of the copy of the order of retention of seized property and the material by the Adjudicating Authority. – (1)

On receipt of the outer sealed envelope along with Form-II, the Adjudicating Authority or in his absence, the designated officer of the office of Adjudicating Authority shall forward Form-II duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding the Form-II to the authorised officer as a token of receipt of the sealed envelope.

(2) The Adjudicating Authority shall, on opening of the sealed envelope, forward Form-I duly filled in, signed and his name legibly written below his signature. The seal of the office of the Adjudicating Authority shall be affixed before forwarding the Form-I to the authorised officer as a token of receipt of the copy of the order of retention of seized property and the material.

(3) The Adjudicating Authority shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register, and register showing details of receipt of the copy of the order of retention along with the material for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the registers immediately on receipt of such order and the material.

5. Period of keeping the copy of the order of retention and the material by the Adjudicating Authority. – The Adjudicating Authority shall keep the copy of the order of retention of seized property and the material for a period of ten years or if, before the expiry of the said period of ten years, –

- (i) any proceedings under section 8 of the Act have been commenced, until the disposal of such proceedings, or
- (ii) where an appeal has been preferred to the Appellate Tribunal under section 26 of the Act, until the disposal of such appeal by the Appellate Tribunal, or
- (iii) where an appeal has been filed in the High Court under section 42 of the Act, until the disposal of such appeal by the High Court;

whichever is later.

6. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM-I

[See sub-rule (2) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received the copy of the order of retention of seized property and the material bearing Number dated

from on at

[the designation of the authorized officer]

[date]

[time]

[Signature of the Adjudicating Authority]

Date :

[Name of the Adjudicating Authority]

[Office seal]

To

[the designation of the authorized officer]

Address

FORM-II

[See sub-rule (5) of rule 3]

ACKNOWLEDGEMENT SLIP

Serial Number

Received a sealed envelope bearing number dated..... from on

[the designation of the authorized officer] [date]

at.....

[time]

Signature of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority.
.....Name of the Adjudicating
Authority/designated officer
of the office of Adjudicating
Authority.
[Office seal]

To

[the designation of the authorized officer]

Address

[Notification No. 12/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 448(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत से बाहर किसी स्थान से अधिप्रमाणित अभिलेखों की प्राप्ति की रीति के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (भारत से बाहर किसी स्थान से अधिप्रमाणित अभिलेखों की प्राप्ति की रीति) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(2003 का 15) अभिप्रेत है ;
 - (ख) “अभिलेख” से भारत के बाहर किसी स्थान से किसी प्ररूप में प्राप्त और इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से अधिप्रमाणित अभिलेख अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।
- (2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की रीति-

- (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त किसी अभिलेख अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा यदि ऐसा अभिलेख,-
 - (क) अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान या मामलों के अन्वेषण के लिए किसी देश की सरकार के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार या संधि के अधीन किसी पदाभिहित प्राधिकारी से प्राप्त हुआ है, या
 - (ख) जो प्राप्त ऐसे अभिलेख पर लगाई गई, छपी हुई या उस पर या उनको मुद्रांकन और हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित है, किसी ऐसे व्यक्ति

से जो किसी नोटरी संबंधी कार्य करने के लिए राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 3 द्वारा प्राधिकृत है, अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से अधिप्रमाणित समझा जाएगा ।

4. निर्वचन-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[अधिसूचना सं. 13/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 448(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (q) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules for the manner of receiving the records authenticated outside India, namely —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Manner of Receiving the Records authenticated Outside India) Rules, 2005.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) "record" means the record in any form received from any place outside India and authenticated in the manner as specified in these rules;
 - (c) "section" means a section of the Act.
 (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Manner of authentication of records received from outside India.** —
 - (1) For the purposes of sub-section (2) of section 22 of the Act, any record received from the place outside India shall be deemed to be authenticated if such record is received, —

1979 GI/05-12

- (a) from an authority designated under an agreement or treaty entered into by the Central Government with the Government of any country for exchange of information or investigations of cases relating to any offence under the Act, or
- (b) which is purporting to have affixed, impressed or submitted thereon or thereto the seal and signature of any person who is authorised by section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) to do any notarial acts shall be deemed to be duly authenticated for the purposes of sub-section (2) of section 22 of the Act.

4. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

[Notification No. 13/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 449(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 35 के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (द) और खंड (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अपील) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**-- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) “न्याय निर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) “अपील अधिकरण” से अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) “अपीलार्थी” से वह व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करे ;

(ङ) “निदेशक” से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत हैं ;

(च) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) “आदेश” से, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक द्वारा या अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अभिप्रेत है ;

(ज) “रजिस्ट्रार” से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. **अपील का प्ररूप-** (1) अधिनियम की धारा 26 के अधीन, यथास्थिति, न्याय निर्णायक प्राधिकारी या निदेशक के विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष की गई प्रत्येक अपील इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगी और अपील चार प्रतियों में होगी और उसके साथ उस आदेश की चार प्रतियां भी होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(2) फाइल करते समय, प्रत्येक अपील के साथ नीचे सारणी में दी गई फीस की रकम, रजिस्ट्रार, अपील अधिकरण, नई दिल्ली के हक में संदेय डिमांड ड्राफ्ट के प्ररूप में होगी ।

सारणी

क्र०सं०	अधिरोपित जुर्माने की रकम	संदेय फीस की रकम
1.	जहां अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम 10,000 रु० है ।	1,000 रु०
2.	जहां अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम 10,000 रु० से अधिक और 50,000 रु० तक है ।	2,500 रु०
3.	जहां अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम 50,000 रु० से अधिक और 1 लाख रु० तक है ।	5,000 रु०
किसी संपत्ति की कुर्की या अभिगृहीत संपत्ति य अभिलेख के प्रतिधारण के विरुद्ध		
4.	जहां अपील अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध है ।	10,000 रु०

(3) अपील में, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर आक्षेप के आधारों का संक्षिप्त रूप से और भिन्न शीर्षकों के अधीन वर्णन किया जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमबद्ध रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तामील का पता, जिस पर अपीलार्थी को अपील अधिकरण की सूचना या अन्य प्रक्रिया की तामिली की जाएगी

तथा वह तारीख जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को तामील किया गया है, विनिर्दिष्ट होगी।

(4) जहां अपील अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है वहां उसके साथ चार प्रतियों में, सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेजों, यदि कोई हों, से समर्थित अर्जी होगी, जिसका अपीलार्थी ने अवलंब लिया है, और उसमें वे कारण दर्शित किए जाएंगे कि अपीलार्थी को पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से कैसे निवारित हुआ था।

(5) कोई सूचना जिसकी तामील अपीलार्थी पर अपेक्षित है, इन नियमों के नियम 5 में विहित रीति से अपील में विनिर्दिष्ट तामील के पते पर तामील की जाएगी।

4. **अपील अधिकरण का आदेश--** अपील अधिकरण का आदेश लिखित में होगा और उसमें विनिश्चय के कारणों का विवरण होगा।

5. **सूचना, अध्यपेक्षाओं या आदेशों की तामील--** इन नियमों के अधीन जारी किसी सूचना, अध्यपेक्षा या आदेश की किसी व्यक्ति पर तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी :--

(क) उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश का परिदान करके या निविदत्त करके ; या

(ख) सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश को अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसको, उसके स्थान या निवास के पते पर या उसके अंतिम रूप से ज्ञात स्थान या निवास या उस स्थान पर जहां वह कारबार करता है अंतिम बार किया है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार किया है, भेज करके ; या

(ग) उस स्थान पर, जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम बार निवास करना ज्ञात है या कारबार करता है या व्यक्तिगत कार्य या लाभ के लिए कार्य करता है, के बाहरी द्वारा पर या परिसर के किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपका करके और उसकी लिखित रिपोर्ट पर दो व्यक्तियों का साक्ष्य लिया जाएगा ; या

(घ) यदि खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश की तामील नहीं की जा सकती है, तो मुख्य अखबार (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके जिसका उस क्षेत्र अधिकारिता में, जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम बार निवास करना ज्ञात है या कारबार करता है या व्यक्तिगत कार्य करता है या लाभ के लिए अंतिम बार कार्य किया है, में, व्यापक प्रकाशन है।

6. **निर्वचन--** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उस विषय को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप

[नियम 3 का उपनियम (1) देखिए]

.....से

(यहां अपीलार्थी का नाम और पते का उल्लेख करें)

सेवा में

रजिस्ट्रार,

अपील अधिकरण

(पता)

महोदय,

ऊपर नामित अपीलार्थी, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 26 के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन निदेशक या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (जो लागू न हो, उसे काट दें) द्वारा दिए गए आदेश संख्या.....तारीख.....के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर अपील करना चाहता है।

तथ्य

(यहां मामले के तथ्यों को संक्षिप्त रूप में उल्लेख करें। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या निदेशक (जो लागू न हो, उसे काट दें) द्वारा दिए गए आदेश की प्रति या अन्य सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति संलग्न करें)

आधार

(यहां उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)।

प्रार्थना

जो भी ऊपर कथित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है :-

चाहा गया अनुतोष

(चाहा गया अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

घोषणा

इस अपील के लिए इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) में दी गई सारणी में यथादर्शित संदेय फीस, रजिस्ट्रार, अपील अधिकरण, नई दिल्ली को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, रसीद संख्या.....तारीख.....द्वारा निक्षेपित कर दी गई है।

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

(अपीलार्थी का नाम)

दस्तावेजों की सूची :

स्थान :

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

तारीख :

(अपीलार्थी का नाम)

[अधिसूचना सं. 14/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (r) and clause (x) of sub-section (2) of section 73 read with section 35 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules for the purpose of appeals under the said Act, namely:-

1. **Short title and commencement.** – These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Appeal) Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
 - (a) “Act” means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

- (b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
 - (c) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal established under section 25 of the Act;
 - (d) "Appellant" means an aggrieved person who prefers an appeal before the Appellate Tribunal;
 - (e) "Director" means the Director appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act;
 - (f) "Form" means the form appended to these rules;
 - (g) "order" means an order passed by the Director under sub-section (2) of section 13 of the Act or by the Adjudicating Authority under section 8 of the Act, as the case may be;
 - (h) "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal;
 - (i) "section" means a section of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Form of Appeal.** – (1) Every appeal preferred before the Appellate Tribunal against the order of the Adjudicating Authority or the Director, as the case may be, under section 26 of the Act shall be in the Form as appended to these rules and the appeal shall be in quadruplicate and accompanied by four copies of the order appealed against.

- (2) At the time of filing, every appeal shall be accompanied with an amount of fee as given in the Table below, in the form of demand draft payable in favour of the Registrar, Appellate Tribunal, New Delhi.

TABLE

Sl.No.	Amount of fine imposed	Amount of fee payable
1.	Where the amount of fine imposed under sub-section (2) of section 13 of the Act is Rs. 10,000/-	Rs. 1,000/-
2.	Where the amount of fine imposed under sub-section (2) of section 13 of the Act is more than Rs. 10,000/- and upto Rs. 50,000/-	Rs. 2,500/-
3.	Where the amount of fine imposed under sub-section (2) of section 13 of the Act is more than Rs. 50,000/- and upto Rs. 1 lakh.	Rs. 5,000/-

Appeal against attachment of any property or retention of the seized property or record.		
4	Where appeal is against the orders made by the Adjudicating Authority under sub-section (3) or sub-section (6) of section 8 of the Act.	Rs. 10,000/-

- (3) The appeal shall set forth concisely and under distinct head the grounds of objection to the order appealed against and such grounds shall be numbered consecutively; and shall specify the address of service at which notice or other processes of the Appellate Tribunal may be served on the appellant and the date on which the order appealed against was served on the appellant.
 - (4) Where the appeal is preferred after the expiry of the period of forty-five days referred to in sub-section (3) of section 26 of the Act, it shall be accompanied by a petition, in quadruplicate, duly verified and supported by the documents, if any, relied upon by the appellant, showing cause as to how the appellant had been prevented from preferring the appeal within the period of forty-five days.
 - (5) Any notice required to be served on the appellant shall be served on him in the manner prescribed in rule 5 of these rules at the address of service specified in the appeal.
4. **Order of the Appellate Tribunal.**— The order of the Appellate Tribunal shall be in writing and shall state the reasons for the decision.
 5. **Service of notice, requisitions or orders.**— A notice, requisition or an order issued under these rules shall be served on any person in the following manner:—
 - (a) by delivering or tendering the notice or requisition or order to that person or the person duly authorized by him; or
 - (b) by sending the notice or requisition or order to him by registered post with acknowledgement due to the address of his place or residence or his last known place or residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
 - (c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons; or
 - (d) if the notice or requisition or order cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), then by publishing in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide

circulation in the area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

6. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM

[See sub-rule (1) of rule 3]

From _____
(Mention name and address of the appellant here).

To

The Registrar,
Appellate Tribunal
(Address)

Sir,

The above-named appellant, begs to prefer this appeal under section 26 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 against order Number _____ dated _____ passed by the Director or the Adjudicating Authority (*strike out whichever is inapplicable*) under the said Act on the following facts and grounds.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose copy of the order passed by the Director or Adjudicating Authority (*strike out whichever is inapplicable*) and copies of other relevant documents, if any.)

GROUND S

(Mention here the grounds on which appeal is preferred).

PRAYER

In the light of what is stated above, the appellant prays for the following relief :-

RELIEF SOUGHT

(Specify the relief sought)

DECLARATION

The fee payable for this appeal as shown in Table given in sub-rule (2) of rule 3 of these rules has been deposited in the form of demand draft with the Registrar, Appellate Tribunal, New Delhi vide receipt number _____ dated _____.

(Signature of the Appellant)

(Name of the Appellant)

List of documents :

Place :

Date :

(Signature of the Appellant)

[Notification No. 14/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.